साप्ताहिक

शहर सत्ता

PRGI NO. CTHIN/25/A2378

सोमवार, 12 जनवरी से 18 जनवरी 2025

हम दिखाएंगे आईना...

वर्ष : 01 अंक : 45 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 03 में...

सब हैं एक से बढ़कर एक...

पेज 09 में...

छत्तीसगढ़ में केंद्र के बराबर मिलेगा भत्ता

पेज 12 दो के बाद चार पैर वाले चूहे खा गए धान...

सत्ता की साख पर बट्टा

रोवर–रेंजर जंबूरी में गड़बड़ी, 5 करोड़ के काम में 2 करोड़ सिर्फ टॉयलेट पर खर्च

टेंट, भोजन, टॉयलेट, बिजली, फोटोग्राफी के लिए टेंडर 5 जनवरी 2026 हुआ

6 करोड़ के काम में 2 करोड़ सिर्फ अस्थायी शौचालय के नाम पर किया जायेगा व्यय

दिसंबर 2025 से ही ठेकेदार करने लगा था काम और 5 जनवरी को वर्क ऑर्डर जारी

सांसद बृजमोहन ने संस्था की स्वायत्तता, वित्तीय नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप

संवाददाता/प्रकाश जोशी
मोबाईल नंबर 9329807462

छत्तीसगढ़ में पहली दफा होने वाला राष्ट्रीय जंबूरी आयोजन विवाद में घिर गया है। वक्त पर इसके नहीं होने पर एक तरह से सुशासन की साख पर बट्टा है। यह खुलासा अगर विपक्ष करता तो एक बात थी। लेकिन प्रदेश भाजपा सरकार के सबसे वरिष्ठ नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुशासन में किये जा रहे कथित घोटाले का मुद्दा उठाया है। फ़िलहाल आयोजन और खर्च की गई राशि से लेकर पैसों के आवंटन को लेकर खफा सांसद बृजमोहन कोर्ट की शरण में हैं। ऐसे में गड़बड़ी पर राज्य सरकार ने अपनी बचाव के लिए नया तर्क दिया है। जिसमें कहा गया है कि भारत स्काउट एंड गाइड का जेम में रजिस्ट्रेशन नहीं है इस कारण सारा काम एक समिति की स्वीकृति के जरिए करवाया जा रहा है। नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी आयोजन में टेंडर गड़बड़ी पर राज्य सरकार ने अपनी बचाव के लिए नया तर्क दिया है। जिसमें कहा गया है कि भारत स्काउट एंड गाइड का जेम में रजिस्ट्रेशन नहीं है इस कारण सारा काम एक समिति की स्वीकृति के जरिए करवाया जा रहा है। बता दें कि 4 दिन के इस आयोजन में 10 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसपर शुरुआती दिन से ही गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद को लेकर दो दावेदार आमने-सामने हैं, आयोजन स्थगित करने का ऐलान हो चुका है और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।

शहर सत्ता/रायपुर। बालोद जिले के ग्राम दुधली में आयोजित राष्ट्रीय रोवर–रेंजर जंबूरी गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों में घिर गई है। आयोजन से जुड़े टेंट, भोजन, टॉयलेट, बिजली, फोटोग्राफी और अन्य व्यवस्थाओं के लिए टेंडर 5 जनवरी 2026 को खोला गया, लेकिन जिस अमर भारत किराया भंडार रायपुर को यह काम मिला उसने एक महीने पहले से ही आयोजन स्थल पर काम शुरू कर दिया था। जसपाल को इसका टेंडर मिला है जो सत्ताधारी दल के एक प्रभावशाली नेता के करीबी बताए जा रहे हैं। सबसे खास बात ये है कि लगभग 6 करोड़ के काम में 2 करोड़ सिर्फ अस्थायी टॉयलेट बनाने पर खर्च किए गए हैं।

स्थानीय स्तर पर उपलब्ध तस्वीरों और वीडियो से साफ है कि दिसंबर 2025 से ही टेंट, अस्थायी टॉयलेट, मंच और अन्य संरचना बनाने का काम शुरू हो गया था। जबकि आधिकारिक रूप से उसी फर्म को 5 जनवरी को वर्क ऑर्डर जारी हुआ। इससे यह समझा जा सकता है कि टेंडर प्रक्रिया केवल औपचारिकता थी और ठेका पहले से हो चुका था। अस्थाई टायलेट पर दो करोड़ के टायलेट बनाए गए :इसी तरह टेंडर दस्तावेजों में दर्शाई गई दरें भी चौंकाने वाली हैं। एक सामान्य टॉयलेट का रेट 22 हजार रुपए रखा गया है और ऐसे 400 टॉयलेट बनाए गए हैं, यानी केवल इस मद में करीब 88 लाख रुपए का खर्च हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी राशि में स्थायी आरसीसी टॉयलेट बनाए जा सकते हैं, न कि अस्थायी ढांचे।

ऐसे छिड़ा घमासान और विवाद

विवाद की जड़ 13 दिसंबर 2025 को जारी वह आदेश माना जा रहा है, जो शिक्षा मंत्री के खेमे से मीडिया को भेजा गया था। इस आदेश में गजेंद्र यादव को स्काउट्स एंड गाइड का पदेन अध्यक्ष मनोनीत बताया गया था। इसके बाद आयोजन के अधिकार, वित्तीय नियंत्रण और निर्णय लेने की शक्तियों को लेकर संगठन के भीतर खींचतान खुलकर सामने आ गई।

इसके अलावा वीआईपी और वीवीआईपी टॉयलेट, यूरिनल और वॉशरूम मिलाकर यह खर्च दो करोड़ रुपए से अधिक पहुंचता है। यही नहीं, वीआईपी कुर्सियां, डिनर टेबल, टेंट, चेयर कवर और वॉशबेसिन जैसी मदों में भी बाजार भाव से कई गुना ज्यादा दरें तय की गई हैं। 340 टेंट के लिए 19 हजार रुपए प्रति टेंट और 100 वीआईपी डिनर टेबल के लिए 12,500 रुपए प्रति टेबल जैसी दरें टेंडर में दर्ज हैं।

दोनों दिग्गज आमने-सामने

"स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने पहले कहा था कि मैं हूं अध्यक्ष। एनएसएस के वार्षिक आयोजन का कैलेंडर सालभर के लिए तैयार होता है। इसलिए हड़बड़ी और गड़बड़ी का कोई सवाल ही नहीं उठता।"

"सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा— "मैं भारत स्काउट गाइड की राज्य परिषद का अध्यक्ष हूं। ऐसे में अध्यक्ष होने के नाते मैं इस कार्यक्रम को स्थगित करता हूं। आयोजन के बारे में मुझे कोई जानकारी तक नहीं दी गई।"

बिना विधिवत टेंडर खुले दे दिया काम

दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने टेंडर को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद इस आयोजन को स्थगित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ रुपये की राशि सीधे जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद के खाते में स्थानांतरित किया गया, जो संस्था की स्वायत्तता और वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। इसी तरह बिना विधिवत टेंडर खुले निर्माण कार्य शुरू करने की बात भी उन्होंने कही थी।

सवालों पर सरकार की हामी

- **बालोद जिले में आज से शुरु इस राष्ट्रीय आयोजन खर्च को लेकर उठे सवालों पर सरकार ने स्वीकार किया है कि इस आयोजन के लिए जेम के माध्यम से टेंडर नहीं किया गया। सरकार का तर्क है कि एनएसएस की राष्ट्रीय इकाई यानी भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की नेशनल बॉडी का जेम पोर्टल पर पंजीकरण नहीं होने के कारण यह प्रक्रिया अपनाना संभव नहीं था।**
- **26 नवंबर 2025 को एनएसएस ने डीपीआई को पत्र लिखकर बता दिया था कि राष्ट्रीय संस्था का जेम आईडी पंजीकृत नहीं होने के कारण टेंडर प्रक्रिया में देरी हो रही है। ऐसे में व्यवस्थाओं के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद को अधिकृत करने का निवेदन किया गया। इसके बाद यह काम शुरु हुआ।**

10 करोड़ में आयोजन

दरअसल, बालोद जिले के दुहली में 9 से 13 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय जंबूरी में लगभग 12 हजार रोवर और रेंजर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा विदेशों से भी रोवर, रेंजर और ऑफिशियल्स के आने की सूचना है। इनके लिए बिजली, पानी, आवास सहित सभी आवश्यक तैयारियां राज्य इकाई द्वारा की गई हैं, देशभर से लगभग 1500 स्टाफ की तैनाती की गई है। शासन द्वारा जंबूरी के लिए कुल 10 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 5 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है, जबकि शेष 5 करोड़ रुपये की मांग शासन से की गई है।

सवाल जस का तस

राज्य सरकार ने टेंडर विवाद पर सफाई तैयार कर ली है लेकिन इस सफाई ने नया सवाल उठा दिया है। वह यह कि भारत स्काउट्स एंड गाइड 1969 की संस्था है। हर साल कई बड़े आयोजन करती है। प्रत्येक आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। क्या उन सभी के लिए नियमों को दरकिनार कर खरीदी की जाती है?

समिति के जरिए स्वीकृति

टेंडर प्रक्रिया को लेकर सरकार का कहना है कि टेंडर की शर्तों के निर्धारण के लिए कलेक्टर बालोद ने क्रय समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष अपर कलेक्टर, एडीएम बालोद हैं, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी सचिव के रूप में शामिल हैं। अध्यक्ष और सचिव सहित कुल नौ सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो टेंडर से संबंधित सभी प्रक्रियाओं की निगरानी कर रही है।

CM साय ने डिलीट किया कार्यक्रम का पोस्ट

विवाद बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए जंबूरी आयोजन से जुड़े पोस्ट को डिलीट किए जाने से भी अटकलें तेज हो गई हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं।

सब हैं एक से बढ़कर एक...

प्रेस क्लब रायपुर चुनाव 2026

पैनलों में सत्ता के करीबी तो कोई आक्रामक

13 जनवरी को पत्रकार चुनेंगे अपना नेता

- 5 पदों के लिए 37 प्रत्याशी मैदान में
- शाम 4 बजे तक डाल सकेंगे सदस्य वोट
- युवा, अनुभवी, खाटी, आदतन नेताओं में भिड़ंत
- एक वर्ष का कार्यकाल और सभी के दावे-वादे बेशुमार

प्रेस क्लब रायपुर के प्रमुख बिंदु

- क्लब की स्थापना 1 जून 1967
- वर्तमान सदस्य संख्या 784
- नाम मधुकर खेर स्मृति भवन
- 13 जनवरी 2026 को मतदान
- मतदान सुबह 8 से शाम 4 बजे तक
- 5 पदों के लिए 37 प्रत्याशी मैदान में
- 6 प्रमुख पैनल और निर्दलीय प्रत्याशी हैं

इन पदों के लिए होंगे चुनाव

- 1 अध्यक्ष पद
- 1 उपाध्यक्ष पद
- 1 महासचिव पद
- 1 कोषाध्यक्ष पद
- 2 संयुक्त सचिव पद

आगामी मंगलवार 13 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पत्रकारों के नेताओं के बीच चुनावी भिड़ंत होगी। प्रेस क्लब रायपुर के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में इस बार युवा, ऊर्जावान लेकिन नव-अनुभवी अध्यक्ष प्रत्याशियों से लेकर सत्ता और सियासी पार्टियों के साथ हनीमून मना रहे अनुभवी, खाटी और चंद पेशेवर नेता भी किस्मत आजमा रहे हैं। हर साल होने वाला प्रेस क्लब का चुनाव इस बार 9 महीने विलंब से हो रहा है। इसलिए भी पत्रकारों और प्रेस क्लब सदस्यों में उत्साह के साथ चुनावी मैदान में उतरे पैनलों के प्रत्याशियों को लेकर खासी चर्चा है। चुनावी चर्चा की एक आला वजह चुनाव में अपनी जीत को लेकर किये जा रहे प्रचार से लेकर खिलाने-पिलाने में पानी की तरह पैसा बहाने वाले पैनल पप्रत्याशी भी हैं। बुद्धिजीवियों के इस चुनाव में धनबल, बाहुबल की जीत होगी या फिर वरिष्ठ संस्थापक सदस्यों द्वारा निर्मित प्रेस क्लब के संविधान का सम्मान करने वाले जीतेंगे इसका जवाब वक्त के गर्त में है।

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब चुनाव के लिए 13 जनवरी 2026 को वोट डाला जाएगा। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रेस क्लब परिसर में ही होगी। मतदान खत्म होते ही उसी दिन मतगणना की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। चुनाव को लेकर प्रेस क्लब के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 1 जनवरी 2026 को किया गया था। दावा आपत्ति की अवधि में 114 सदस्यों से आपत्तियां मिली, जिनका विधिवत निराकरण कर 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई। इसके बाद 6 से 8 जनवरी तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पदों के लिए कुल 38 नामांकन मिले। 9 जनवरी को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की गई, जिसमें सभी नामांकन वैध पाए गए। इसके पश्चात 10 जनवरी को नाम वापसी की प्रक्रिया में संयुक्त सचिव पद से एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। नाम वापसी के बाद अब कुल 5 पदों के लिए 37 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और सभी प्रत्याशी मतदाताओं को एकजुट करने में जुट गए हैं।

परंपरा को संवारने के नाम पर लगाया पलीता

एक समय में प्रेस क्लब रायपुर में सदस्यों मतदाताओं की संख्या उपलब्ध संसाधनों के अनुसार थी। पहले अध्यक्ष और महासचिव पद का निर्वाचन सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर पूर्ण हो जाता था। लेकिन समय के साथ राजनीतिक लक्ष्यों के लिए फिर अपने- अपने चेहतों को थोक में सदस्यता देने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि प्रेस क्लब संविधान जब बनाया गया था तब इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मिडिया का वजूद नहीं था। उस वक्त मिडिया संस्थानों की संख्या भी सिमित थी। धीरे धीरे वक्त पलटा और सदस्यों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई और इसके साथ ही चुनावों में पैसों की फिजूलखर्ची सीमा की पराकाष्ठा पार करने लगी। अब एक-एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव कोषाध्यक्ष प्रत्याशी और दो संयुक्त सचिव पद के लिए निर्वाचन होने लगा है। पुराने समय में सिर्फ अध्यक्ष-महासचिव चुने जाते थे और पूरी कार्यकारिणी फिर दोनों पदाधिकारी चुनते थे। अब 5 पदों और ढेर सारे पैनलों के साथ मतदाता संख्या भी बेतहाशा हो गई है। ऐसे में विवादों, आपसी लांछन लगाने और मतदाताओं को लुभाने की बदतरीन परंपरा प्रेस क्लब सदस्यों और पत्रकारों की एकता को नेस्तनाबूद कर रही है। ऐसों को शह देने में खबरनवीस भी और चंद अख़बार मालिक भी शुमार हैं।

मैदान में अध्यक्ष पद के ये दावेदार

सर्व एकता पैनल से अध्यक्ष प्रत्याशी कृष्ण कुमार शर्मा(के.के. शर्मा) हैं। सरल, सहज और अनुभवी पत्रकार वर्तमान में दैनिक अग्रदूत के संपादक हैं। रायपुर प्रेस क्लब में एकमात्र के.के. शर्मा ही ऐसे पदाधिकारी रहे हैं जिन्होंने संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष से लेकर महासचिव और अध्यक्ष पद में निरंतर रहे। वे वर्ष 2017-18 में सबसे सफल और संवैधानिक प्रक्रिया निभाने वाले अध्यक्षीय कार्यकाल निभाए। पैनल से महासचिव पद पर युवा, ऊर्जावान और पत्रकारों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले दानिश अनवर भास्कर, नवभारत, पत्रिका, हरिभूमि में बतौर पत्रकार रहे। वर्तमान में डिजिटल मिडिया 'द लेंस' में सीनियर रिपोर्टर हैं।

परिवर्तन पैनल से भी पूर्व में महासचिव रहे प्रशांत दुबे इस बार अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। मिलनसार और अच्छी-सच्ची पत्रकारिता करने वाले अध्यक्ष प्रत्याशी प्रशांत दुबे की साख में एक बट्टा उनके महासचिव कार्यकाल का है। वर्ष 2018-19 में पूर्व अध्यक्ष दामू आंबेडारे असंवैधानिक तरीके से करीब 5 वर्षों तक कब्जा जमाये रहे तो महासचिव प्रशांत ने दमदारी नहीं दिखाई और बिना आय-व्यय का ब्यौरा दिए खुद को अब अध्यक्ष बनकर प्रेस क्लब की गरिमा लौटाने का दावा कर मैदान में हैं। उनके पैनल से महासचिव पद पर प्रत्याशी पराग मिश्रा हैं।

संगवारी पैनल से अध्यक्ष प्रत्याशी युवा, अनुभवी और इलेक्ट्रॉनिक मिडिया से राज्य अलंकरण प्राप्त पत्रकार हैं। सरल, सहज और मृदुभाषी हैं लेकिन नए मतदाताओं के बीच उनकी नाराजगी है। पिछले 9 महीने के विवादित कार्यकाल में संविधान संशोधन और नए मतदाताओं की सूचि का विरोध करते हुए फार्म सोसायटी तक आपत्ति करने से उन्हें युवा पत्रकारों का विरोधी माना जाने लगा है। अनुभवी और सरल हिर्दय पत्रकार महासचिव पद के दावेदार गौरव शर्मा हैं। अच्छी इमेज और खबरों के लिए जाने जाते हैं लेकिन लंबे समय तक प्रेस क्लब से दूरी बनाने का उन्हें नुकसान होगा।

संकल्प पैनल में अध्यक्ष पद प्रत्याशी प्रफुल्ल ठाकुर और महासचिव पद प्रत्याशी संदीप शुक्ला हैं। लगातार दूसरी बार प्रफुल्ल अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं और संदीप उपाध्यक्ष थे अब महासचिव प्रत्याशी हैं। दोनों ही प्रेस क्लब की गरिमा, संविधान का पालन और नए पत्रकार सदस्यों को मताधिकार के प्रबल समर्थक हैं। लेकिन इनके 1 वर्ष के कार्यकाल और 9 महीने के अवैध कार्यकाल में लिए गए 125 वरिष्ठ सदस्यों का नाम काटने नए नाम गलत प्रक्रिया से जोड़ने और बेतहाशा सदस्यता शुल्क वसूलने को लेकर सदस्यों मतदाताओं में खासी।

प्रतिष्ठा पैनल में एकमात्र सर्वविदित और जाना पहचाना नाम हैं अनिल पुसदकर का। वरिष्ठ पत्रकार और तल्ख़ लेखनी के साथ आक्रामक व्यक्तित्व से इन्हें एक दशक तक रायपुर प्रेस क्लब में बतौर अध्यक्ष बनने का मौका मिला। इस दौरान पत्रकारों के लिए आवासऔर पत्रकारों सदस्यों को प्रेस क्लब से आर्थिक मदद देने से पहचान बनी। लेकिन, अध्यक्ष बनने के बाद एक वर्ष के कार्यकाल को मन माफिक मियाद तक बढ़ाने से छवि भी धुमिल हुई। फ़िलहाल पूरवर्ती दो अवैध कार्यकालों और वरिष्ठों के नाम काटे जाने पर भी इनकी रहस्यमय ख़ामोशी साथियों को भी नागवार गुजरी है। वर्तमान में एक बार फिर प्रेस क्लब सदस्यों का मुखिया बताकर चुनावी मैदान में हैं। उनके साथ पुनः वरिष्ठ प्रेस छायाकार महादेव तिवारी भी महासचिव पद पर दांव आजमा रहे हैं।

क्रांतिकारी पैनल से पहली बार अध्यक्ष पद की दावेदारी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव और महासचिव के लिए सुरेंद्र शुक्ला दावेदारी कर रहे हैं। सुनील नामदेव तेज तर्राट और आक्रामक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। सुरेंद्र शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं और सरल व्यक्तित्व के धनि हैं। लीडिंग अख़बारों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नीभाये हैं फ़िलहाल वे हरिभूमि में हैं।

साप्ताहिक शहर सत्ता

युवा संसद में जब डॉ. रमन बने अध्यक्ष और बच्चे सांसद

लोकतंत्र की पाठशाला बना नेशनल रोवर-रेंजर जंबूरी, दिखी भविष्य के नेतृत्व की सशक्त झलक

नेशनल रोवर - रेंजर जंबूरी का आयोजन पूरे उत्साह, अनुशासन और जीवंत सहभागिता के साथ बालोद जिले के ग्राम दुधली में सम्पन्न किया रहा है। आयोजन के तीसरे दिन जंबूरी परिसर लोकतांत्रिक चेतना का केंद्र बन गया, जब रोवर–रेंजरों एवं उपस्थित नागरिकों को लोकसभा की वास्तविक कार्यवाही का प्रत्यक्ष और व्यावहारिक अनुभव कराया गया। यूथ पार्लियामेंट के मंच पर रोवर–रेंजरों ने सांसदों की भूमिका निभाई वहीं विधानसभा के अध्यक्ष संसद के अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। युवाओं ने जिस आत्मविश्वास, विषयगत समझ और मर्यादित संवाद शैली का प्रदर्शन किया, वह दर्शनीय था। यह मंच भावी जनप्रतिनिधियों को गढ़ने का सशक्त माध्यम गया था।

अनुशासन और आत्मविश्वास की मिसाल बने रोवर–रेंजर

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की आयोजित युवा संसद की सराहना करते हुए कहा कि यूथ पार्लियामेंट के दौरान रोवर–रेंजरों जिस प्रकार आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ अपनी भूमिका को निभाया है, उससे देश के उज्वल भविष्य की कल्पना साकार नजर आती है। आज के युवा कल के हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं। इनके कंधों पर हमारी विरासतों को आगे ले जाने का जिम्मा है, जिसे वे बखूबी निभाएंगे इसका हम सभी को भरोसा है।

उन्होंने सभी की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और जिम्मेदार नागरिकता की मजबूत नींव पड़ती है। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज के रोवर - रेंजर देश का आने वाला भविष्य है। भारतीय स्काउट गाइड के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के. के. खंडेलवाल, राज्य मुख्य आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह खालसा, जिला मुख्य आयुक्त श्री राकेश यादव, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, रोवर–रेंजर, स्काउट–गाइड्स एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।

सीख, सेवा और साहस से भरा रहा तीसरा दिन

जंबूरी का तृतीय दिवस प्रतिभागियों के लिए विविध और प्रेरक गतिविधियों का आयोजन किया गया। जागरण और शारीरिक जांच के साथ फ्लैग सेरेमनी के साथ अनुशासन और एकता का संदेश दिया जाएगा। डॉग शो में कुत्तों की बेहतरीन कलात्मक प्रदर्शन के साथ मार्च पास्ट प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी प्रतियोगिताओं में भी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया। आज जम्बूरी में आदिवासी संस्कृति परंपरा के साथ आधुनिकता की अनूठी प्रस्तुति दी गयी। आदिवासी वेशभूषा में पारंपरिक व्यंजनों के निर्माण के साथ लोकवाद्यों की भी प्रस्तुति की गई। आदिवासी नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच पारंपरिक भोजन के साथ ही हॉर्स राइडिंग, बाइक रेस और वाटर एक्टिविटी जैसी साहसिक गतिविधियां का भी प्रदर्शन किया गया।

युवाओं को आपदा प्रबंधन और ग्लोबल डेवलपमेंट विलेज से जुड़ी प्रतियोगिताओं के साथ वृक्षारोपण भी किया गया। कंटीजेंट लीडर मीटिंग, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, एच डब्लू बी रीयूनियन, नाइट हाईक तथा पायोनियरिंग प्रोजेक्ट प्रतियोगिताओं के भी आयोजित की जाएगी। एरिना में आयोजित इंटरनेशनल नाइट कार्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों की रंगारंग प्रस्तुतियां जंबूरी को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

कलेक्टर दीपक सोनी को केन्द्र में मिली नियुक्ति

रायपुर। बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर दीपक सोनी को केन्द्र में पोस्टिंग मिली है. केंद्र सरकार ने उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में डायरेक्टर बनाया है. नियुक्ति की अवधि पांच वर्ष अथवा आगामी आदेश तक है. राज्य सरकार की सहमति पर दी गई थी. दिल्ली में उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान पद से मुक्त किए जाने के तीन सप्ताह के भीतर उन्हें नए पद पर ज्वाइन करना होगा।

यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ कैडर के लिए भी गौरव का विषय मानी जा रही है। संयोग से 2011 बैच के एक अन्य अधिकारी सर्वेश भूरे भी हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। दो अधिकारियों का एक साथ केंद्र में चयन छत्तीसगढ़ कैडर की प्रशासनिक क्षमता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। भारत सरकार ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र भेजते हुए दीपक सोनी को तत्काल प्रभाव से वर्तमान पद से रिलीव करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होते ही वे दिल्ली पहुंचकर नई जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके रिलीव होने के बाद बलौदाबाजार जिले को नया कलेक्टर मिलेगा।

राजस्व मामलों के निपटारे, सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन और समयबद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर उन्होंने जिले में कार्यसंस्कृति को नई दिशा दी। जिले में आम नागरिकों तक सीधी पहुंच के लिए उन्होंने जनसंवाद केंद्र की शुरुआत की, जिसकी सराहना रायपुर संभाग के संभागायुक्त महादेव कावरे ने भी की थी। दीपक सोनी को बलौदाबाजार जिले की कमान एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण दौर में सौंपी गई थी। 10 जून 2024 को कलेक्ट्रेट परिसर में हुई आगजनी और हिंसा की घटना के बाद जिले की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। हालात को नियंत्रण में लाना शासन के लिए बड़ी प्राथमिकता थी। यह काम दीपक सोनी बखूबी किया। उन्हें इस काम के लिए जाना जाएगा।

पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन बने मुख्य सूचना आयुक्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य सूचना आयोग में अहम नियुक्तियां की हैं। पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। इसी क्रम में सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के पद पर दो अहम नियुक्ति की गई है। इनमें सेवानिवृत्त आईएएस उमेश कुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ पत्रकार डॉ. शिरीष चंद्र मिश्रा शामिल हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सभी नियुक्तियों की सेवा शर्तें, वेतन एवं अन्य भत्ते भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के तहत "सूचना का अधिकार (केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोगों में पदावधि, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019" के अंतर्गत निर्धारित होंगे। उक्त आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार जारी किया गया है।

महिलाओं के डांस पर उड़ाए नोट, एसडीएम की छुट्टी

गरियाबंद जिले में अश्लील डांस करने वाली महिलाओं के डांस पर नोट उड़ाने वाले एसडीएम को हटा दिया गया है। सरकार ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुये मैनपुर एसडीएम तुलसी दास मरकाम को हटाते हुये शो-काॅज नोटिस भी जारी किया है। साथ ही अपर कलेक्टर के नेतृत्व में एक जांच समिति भी गठित की है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और रिपोर्ट कमिश्नर को सौंपेगी।

क्या था पूरा मामला

दरअसल, देवभोग क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में ओडिसा से महिला डांसर्स बुलाई गई थी। आयोजन के नाम पर महिला डांसर ने बेहद ही आपत्तिजनक अश्लील डांस किया। इतना ही नहीं मैनपुर एसडीएम साहब महिला के डांस पर नोट उड़ाते हुए ठुमके लगाते नजर आये। यही नहीं SDM ने मोबाइल से अश्लील डांस का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे मैनपुर एसडीएम का नाम तुलसीदास मरकाम है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कार्यक्रम का जमकर विरोध हो रहा है। लोग वीडियो को शेयर करते हुये एसडीएम व क्षेत्र की पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे है। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस की मौजूदगी में ऐसे अश्लील कार्यक्रम को कैसे होने दिया गया? इस कार्यक्रम से न केवल छत्तीसगढ़ की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ीं, बल्कि कानून व्यवस्था का भी जमकर मजाक उड़ाया गया। बताया जा रहा हैं कि दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच भी किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर, जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

-: आदेश :-

क्रमांक/ 129 /[illegible]/2026 गरियाबंद, दिनांक 11 /01/2026

[illegible]

कलेक्टर,
जिला गरियाबंद

पृ.क्रमांक/ 129-A/[illegible]/2026 गरियाबंद, दिनांक 11 /01/2026

प्रतिलिपि–

01. [illegible]
02. [illegible]
03. [illegible]
04. [illegible]
05. [illegible]
06. [illegible]
07. [illegible]

कलेक्टर
जिला गरियाबंद

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

कफ़न में भी जेब

प्रधानमंत्री मोदी ने जब से कार्यभार संभाला है, तब से ही अर्थात 2014 से लाल किले से दिए गए उनके भाषणों की कुछ बातों का उल्लेख रह-रह कर होता है। ऐसी कुछ घोषणाओं ने तो प्रभावी योजनाओं का रूप भी लिया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय निर्माण, आयुष्मान भारत योजना, कृषि सम्मान निधि, भारत माला आदि। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कुछ न कुछ कहते रहे हैं। 2024 में उन्होंने दो टूक कहा था,'भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई ईमानदारी के साथ जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं उनके लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं। देश के सामान्य नागरिकों को लूटने की जो परंपरा बनी है, उसे मुझे रोकना है।' इसके अलावा वे पीएम बनने के पहले यह भी कह चुके हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। क्या यह कहा जा सकता है कि भ्रष्ट तत्वों के लिए भय के वातावरण का निर्माण हो सका है? इसका सीधा जवाब है-नहीं।

केवल यह कहना ही सही नहीं कि सरकारी क्षेत्र में जहां किसी तरह का निर्माण, वहां भ्रष्टाचार। सच यह भी है कि जहां भी किसी तरह का सरकारी दखल, वहां पैसे लेने-देने का चलन। यदि सरकारी तंत्र को कोई अनुमति-स्वीकृति देनी है या किसी तरह का प्रमाणन या नवीनीकरण करना है तो वह बिना जेब ढीली किए होना मुश्किल है। पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक अब अपने कफ़न में जेब लगाने में लगे हैं। कई बार लोगों के जायज काम भी कुछ दिए बिना नहीं होते और सब जानते हैं कि नाजायज काम होते रहते हैं। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार बढ़ते-बढ़ते इतना व्यापक हो गया है कि वह निजी क्षेत्र में भी घुस गया है। सरकारी क्षेत्र में मलाईदार पदों पर नियुक्तियों, कोई काम या ठेका देने अथवा खरीद में जैसा भ्रष्टाचार है, वैसा ही कुछ-कुछ निजी क्षेत्र में भी है। कमीशनबाजी हर कहीं है। यह है तो दलाली और घूसखोरी ही, पर अब उसे सुविधा शुल्क भी कहते हैं। इसके आधार पर ऐसे निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंचा जाए कि देश-राज्य गड्ढे में जा रहा है अथवा सबके सब सरकारी अधिकारी-और कर्मचारी भ्रष्ट हैं। ऐसा नहीं है।

भारत विरोधाभासों का देश है। अपने यहां कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी भी हैं और वे अपना काम सही तरीके से भी करते हैं। कुछ तो फोन पर भी जनता की शिकायत सुनकर उसका समाधान कर देते हैं, पर यह कहना बहुत कठिन है नौकरशाही में उनकी ही अधिकता है। इसके लिए अभी बहुत कुछ करना है-केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी और सबसे बड़ी बात उनकी नौकरशाही को भी। भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ को प्राथमिकता के आधार पर खत्म करना होगा। यह गठजोड़ स्थानीय निकायों के स्तर पर ही शुरू हो जाता है। यदि सरकारी वेतन बढ़ रहे हैं तो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती भी बढ़ानी होगी। भ्रष्ट तत्वों के मन में सचमुच दंडित होने का भय होना चाहिए, भले ही वे कितने ही उच्च पद पर हों। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाने की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन नतीजा वैसा नहीं, जैसा दिखना चाहिए। अपने देश में भ्रष्ट सरकारी अफसरों-कर्मियों को दंडित करना अब भी कठिन है। शीर्ष स्तर के भ्रष्ट अफसरों को तो दंड देना कुछ ज्यादा ही कठिन है। कई बार नेताओं से भी अधिक। यह ठीक है कि उन्हें एक हद तक संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वे बिना किसी भय और दबाव के फैसले ले सकें, लेकिन इस कवच के दायरे में भ्रष्ट तत्व क्यों आने चाहिए?

हमर देश म कतकों बेर मनाए जाथे नवा बछर..

सुशील भोले

हमर देश ल बहुभाषी बहुसंस्कृति वाले देश कहे जाथे, एकरे सेती इहाँ कतकों परब तिहार के रूप-रंग अउ चलन घलो बहुआयामी देखेब म आथे. ठउका इही बानी नवा बछर ल घलो इहाँ कतकों बेर मनाए जाथे. वइसे जादा करके ए देखे म आथे, के खेती-किसानी ले जुड़े कोनो विशेष परब या बेरा ल ही अलग-अलग संस्कृति म नवा बछर के रूप म मनाए जाथे. आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर म 1 जनवरी ल ही नवा बछर के रूप म मनाए के जादा चलन देखे जावत हे, जेन ह असल म ईसाई धर्म के नवा बछर के शुरुआत आय. 1 जनवरी ल नवा बछर के रूप म मनाए के शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 ले होय रिहिसे. एकर तारीख के गिनती ह ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक होथे. हमर देश मूल रूप ले कृषि प्रधान देश आय. एकरे सेती इहाँ सबो डहर नवा बछर के उछाह कृषि आधारित ही होथे.

अक्ती छत्तीसगढ़ी नवा बछर..

हमर छत्तीसगढ़ म बैसाख महीना म अंजोरी पाख के तीज तिथि म अक्ती के रूप म नवा बछर मनाए जाथे. इही दिन इहाँ खेती-किसानी ले जुड़े जम्मो कमइया संग पौनी-पसारी मनके नवा बछर खातिर नियुक्ति होथे. हमर इहाँ इहिच दिन इहाँ के खरीफ धान के बोवई के शुरुआत घलो होथे, जेला इहाँ के भाषा म 'मुठधरई' या 'मूठ धरना' कहे जाथे. आवव जानथन अइसने अउ कब-कब इहाँ नवा बछर मनाए के परंपरा हे...

नवसंवत्सर-

चैत महीना के अंजोरी पाख म एकम के दिन ल नवा बछर माने जाथे. एला हिन्दू धर्म के नवा बछर के रूप म घलो मनाए जाथे. इहाँ ए जानना जरूरी हे, के भारतीय कैलेंडर के गिनती सूर्य अउ चंद्रमा के आधार म होथे. अइसे मान्यता हे के विक्रमादित्य के बेरा म सबले पहिली भारत म कैलेंडर या पंचाग के चलन शुरू होइस. एकर छोड़े 12 महीना के एक बछर अउ 7 दिन के एक हफ्ता के चलन ल घलो विक्रम संवत ले ही माने जाथे.

उगाडी-

ए नवा बछर ल कर्नाटक अउ आंध्र प्रदेश म मनाए जाथे. एला तेलुगु नवा बछर घलो कहिथें. ए ह हमर हिन्दी के चैत महीना अउ अंग्रेजी के मार्च-अप्रैल के बीच म आथे.

गुड़ी पड़वा-

चैत महीना के अंजोरी पाख म एकम के दिन गुड़ीपड़वा के तिहार ल मनाए जाथे. मराठी अउ कोंकणी लोगन एला नवा बछर के रूप म मनाथें. ए दिन गुड़ी ल घर के मुहाटी म लगाए जाथे.

बैसाखी-

बैसाखी ल पंजाबी नवा बछर घलो कहे जाथे. एला 13 या 14 अप्रैल के मनाए जाथे. एकर मुख्य तिहार खालसा के जन्म स्थान अउ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर म मनाए जाथे. अब तो ए तिहार ल अमेरिका, कनाडा अउ इंग्लैंड के संगे-संग जिहां-जिहां खालसा पंथ ल मानने वाले मन रहिथें उहाँ-उहाँ मनाए जाथे.

पुथंडु-

तमिल महीना Chithirai के पहली दिन, जे ह अप्रैल महीना के बीच म परथे, वो दिन तमिल नवा बछर मनाए जाथे. ए बेरा म लोगन एक-दूसर ल

Puthandu Vazthukal कहिथें. ए दिन कच्चा आमा, गुड़ अउ लीम के फूल ले ए तिहार खातिर विशेष पकवान बनाये जाथे.

बोहाग बिहू-

एला असामी नवा बछर के रूप म जाने जाथे. ए बोहाग बिहू परब ल अप्रैल महीना के बीच म मनाए जाथे. एला असम के सबले बड़का परब के रूप म मनाए जाथे.

पोहला बोईशाख-

एला बंगाली नवा बछर घलो कहिथें. ए ह अप्रैल महीना के बीच म परथे. बंगाल म एला 'पोहला बोईशाख' कहे जाथे. ए ह बैशाख महीना के पहला दिन होथे. पोहला माने पहला अउ बोईशाख ह बंगाली कैलेंडर के पहला महीना आय. बंगाली कैलेंडर ह हिन्दू वैदिक सौर मास ऊपर ही आधारित हे. पश्चिम बंगाल के छोड़े त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्र म घलो पोहला बोईशाख मनाए जाथे.

बेस्तु वर्ष-

एला गुजराती नवा बछर कहे जाथे. गुजराती नवा बछर बेस्तु वर्ष कहे जाथे, एला देवारी बिहान दिन मनाए जाथे. मान्यता हे, के भगवान कृष्ण ह ब्रज म तेज बरखा ल छेंके खातिर गोवर्धन पहाड़ ल उठाय रिहिसे, वोकरे सेती ए दिन गोवर्धन पूजा करे जाथे. गुजराती नवा बछर के शुरुआत इही गोवर्धन पूजा के दिन ल माने जाथे.

विषु-

केरल म मनाए जाने वाला नवा बछर ल 'विषु' के रूप म जाने जाथे. ए ह मलयालम महीना मेदम के पहिली तिथि म आथे. केरल म विषु उत्सव के दिन धान बोआई के बुता के शुरुआत होथे. विषु परब म सबले महत्वपूर्ण होथे- विषुकनी रसम, जेला घर के सबो झन निभाथें. एमा घर के सबो झन बिहनिया सबले पहिली अपन कुल देवी-देवता मनके दर्शन-पूजन करथें.

नवरेह-

कश्मीरी नवा बछर नवरेह ल कश्मीर म नवा चंद्रवर्ष के रूप म मनाए जाथे. एला चैत नवरात के पहला दिन मनाए जाथे. नवरेह के तिहार ल कश्मीरी पंडित मन बड़ उत्साह के साथ मनाथें. नवरेह के बिहनिया सबले पहिली चाऊर ले भरे बर्तन ल देखथें. एला समृद्धि ले भरे भविष्य के प्रतीक माने जाथे.

हिजरी-इस्लामिक नवा बछर-

इस्लामिक नवा बछर मुहर्रम के पहला दिन ले शुरू होथे. हिजरी चंद्रमा आधारित कैलेंडर आय. इस्लामिक धार्मिक परब तिहार मनला मनाए खातिर हिजरी कैलेंडर के ही इस्तेमाल करे जाथे.

सुशील भोले

कोंदा-भैरा के गोठ

-रायगढ़ जिला के तमनार ब्लॉक म जिंदल पॉवर कोयला खदान के खिलाफ प्रदर्शन के बेरा एक महिला आरक्षक के कपड़ा ल चीरे के मुख्य आरोपी चित्रसेन साव के काली पुलिस ह जुलूस निकाले रिहिसे जी भैरा.

-हव जी कोंदा.. महूँ मीडिया के माध्यम ले जुलूस ल देखत रेहेंव.. वोकर करनी के सेती आक्रोशित महिला आरक्षक मन वोला चप्पल के माला पहिरा के वोकर मुँह म चारों मुड़ा लिपस्टिक पोते रिहिन हें अउ 'वर्दी फाड़ना पाप है पुलिस हमारा बाप है' नारा लगवावत न्यायालय तक लेगे रिहिन हें.

-हव जी.. महिला आरक्षक के ए कपड़ा ल चीरे के सेती तो इहाँ के आम लोगन घलो खिसियावत रिहिन हें, फेर मोला अइसे जनाथे संगी के चित्रसेन साव आदि मन के द्वारा वो दिन जेन अभद्रता करे गे रिहिसे वो ह अन्याय ले उपजे आक्रोश ही आय.

-अइसे का?

-हव.. जब शासन के तंत्र म बइठे लोगन नकली जनसुनवाई के नॉव म जनता के खेत-खार अउ जंगल झाड़ी ल कोनो उद्योगपति ल बरपेली सौंपे के षडयंत्र करहीं.. खुलेआम जनता संग अन्याय करहीं त फेर वो ह अउ का करही? आक्रोशित होके अपन मर्यादा ल तो नहाकबे करही ना? मैं ह आरोपी के पक्ष नइ लेवत हौं, फेर सरकार ल अइसन घटना खातिर गंभीरता ले सोचना चाही.

सुविचार- कुछ ऐसा करें कि सपने अशांति का कारण न बनें

नींद भी निराली होती है। कम आए तो बीमारी, ज्यादा आए तो भी बीमारी। नींद का संबंध सपनों से भी है। नींद के सपने बीमारी के लक्षण हैं। जागते हुए सपने देखना संकल्प का प्रतीक है। वैज्ञानिक कहते हैं जब हम सपने देखते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां इधर-उधर घूमती हैं। इसे आरईएम यानी रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं।

कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी बताते हैं कि पुतलियां यदि भीतर ही भीतर घूमें तो सपने आते हैं या सपनों में ऐसा होता है। अब चूंकि अधपकी नींद सपनों की संतानें हैं और नई-नई बीमारियों को जन्म देने वाली हैं, इसलिए दिन में एक प्रयोग किया जा सकता है। कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें, अपनी पुतलियों को भीतर ही भीतर अपने मस्तिष्क में देखें- जैसे छतरी खोलकर भीतर से झांका जा रहा है। उसे सहस्रार चक्र कहते हैं, जहां देखना है। अगर दिन में दो-तीन बार इसका अभ्यास करें तो पुतलियां घूमेंगी नहीं, सपने नहीं आएंगे। या सपनों में पुतलियां नहीं घूमेंगी तो सपने अशांति का कारण नहीं बनेंगे।

क्यूबा पर पड़ी ट्रंप की तिरछी नजर, दी धमकी

वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को धमकी दी है. ट्रंप ने रविवार (11 जनवरी, 2025) को क्यूबा को सुझाव देते हुए कहा कि उन्हें अमेरिका के साथ डील कर लेनी चाहिए, कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वरना क्यूबा का तेल और फंड रोक दिया जाएगा. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'क्यूबा को अब न तो तेल जाएगा और न ही पैसा- शून्य! मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे बहुत देर होने से पहले एक डील साइन कर लें.' ट्रंप ने लिखा, 'क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से मिलने वाले भारी मात्रा में तेल और फंड पर निर्भर रहा. बदले में, क्यूबा ने वेनेजुएला के पिछले दो तानाशाहों को 'सुरक्षा सेवाएं' प्रदान कीं, लेकिन अब और नहीं.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले सप्ताह अमेरिका के हमले में ज्यादातर क्यूबा के लोग मारे गए हैं और वेनेजुएला को अब उन गुंडों और जबरन वसूली करने वालों से सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने उन्हें इतने वर्षों तक बंधक बनाकर रखा था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे लिखा, 'वेनेजुएला के पास अब संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है, जो उनकी रक्षा करेगी और हम उनकी रक्षा करेंगे. क्यूबा को अब और तेल या धन नहीं भेजा जाएगा- शून्य! मेरा सुझाव है कि वे बहुत देर होने से पहले एक समझौता कर लें.'

क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल ने शनिवार (10 जनवरी, 2025) को हवाना में अमेरिकी दूतावास के सामने हजारों लोगों के साथ रैली में वेनेजुएला पर हमला करने और उसके राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए अमेरिका की निंदा की. कैनेल ने कहा, 'क्यूबा इन कार्रवाइयों की निंदा करता है और इन्हें राज्य आतंकवाद का कृत्य मानता है.'उन्होंने आगे कहा, 'यह अंतरराष्ट्रीय कानून के मानदंडों का एक चौंकाने वाला उल्लंघन है- एक शांतिपूर्ण राष्ट्र के खिलाफ सैन्य आक्रामकता जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है.'बता दें कि वेनेजुएला, क्यूबा को करीब 30 फीसदी तेल आपूर्ति करता है, जिसके बदले में उसे क्यूबाई चिकित्सा कर्मी मिलते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल का नुकसान क्यूबा के पहले से ही कमजोर बिजली ग्रिड और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक विनाशकारी झटका होगा. अमेरिका ने बीती तीन जनवरी को वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ़्तार कर लिया. अमेरिका ने कहा कि ये कार्रवाई नशीले पदार्थों की तस्करी के ख़िलाफ थी और उनके खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है. बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है, जोकि करीब 300 अरब बैरल का है.

अगर अमेरिका ने तेहरान में की एयरस्ट्राइक तो क्या करेगा ईरान?

नई दिल्ली। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को चुनौती देने वाले प्रदर्शन बीते कई दिनों से जारी हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका, ईरान की मदद के लिए तैयार है. विरोध-प्रदर्शन की आड़ में अगर अमेरिका ईरान में एयरस्ट्राइक करता है तो तेहरान क्या करेगा? इसका ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है. ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी के अनुसार अमेरिका इस्लामी गणराज्य पर हमला करता है तो तेहरान अमेरिकी सेना और इजराइल को टारगेट करेगा. कालीबाफ ने यह धमकी तब दी जब ईरानी संसद में सांसद 'अमेरिका मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए मंच पर चढ़ गए. विदेशों में रहने वाले लोगों को डर है कि इंटरनेट पर लगी रोक से ईरान की सुरक्षा सेवाओं के भीतर के कट्टरपंथियों को एक खूनी कार्रवाई शुरू करने का हौसला मिलेगा. भले ही ट्रंप ने चेतावनी दी हो कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की रक्षा के लिए ईरान पर हमला करने को तैयार हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए सोशल मीडिया पर कहा, 'ईरान शायद पहले कभी न देखी गई आज़ादी की ओर देख रहा है. अमेरिका मदद के लिए तैयार है.' न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अधिकारियों के हवाले से शनिवार रात को बताया कि ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए सैन्य विकल्प दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया था.विदेश विभाग ने अलग से चेतावनी दी, 'राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ खिलवाड़ न करें. जब वह कुछ करने का वादा करते हैं तो वह उसे पूरा करने का वादा करते हैं।

मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते अजीत डोभाल?

नई दिल्ली। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) अजीत डोभाल मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं. उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी दी. वह विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के उद्घाटन में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने सत्र में पहुंचे युवा प्रतिभागियों को संबोधित किया. कार्यक्रम भारत मंडपम में हो रहा था. जब सत्र के दौरान सवाल जवाब का सेशन चल रहा था तो उनके मोबाइल फोन रखने और इंटरनेट का उपयोग न करने को लेकर सवाल पूछा गया. इस दौरान उन्होंने कहा, 'मैं फोन का भी इस्तेमाल नहीं करता. सिवाय फैमिली और दूसरे देशों के लोगों से बात करता हूं, वो भी तब, जब बात करना बेहद ही जरूरी हो.' डोभाल ने कहा, 'मैं अपना काम इसी तरह मैनेज करता हूं. कम्युनिकेशन के और कई तरीके हैं. कुछ अतिरिक्त तरीके भी अपनाने पड़ते हैं. इस बारे में लोगों के पास जानकारी कम होती है.'

अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं. इस पद पर रहने वाले वह पांचवे व्यक्ति हैं. वह केरल कैडर के एक रिटायर्ड भारतीय पुलिस अधिकारी है. उन्होंने दशकों तक इंटेलिजेंस, इटरनल सिक्योरिटी और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनका जन्म उत्तराखंड में साल 1945 में हुआ था. वह 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं. उन्हें सबसे कम उम्र में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है. डोभाल इस चक्र को पाने वाले सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी हैं.

उन्होंने अपने करियर के दौरान मिजोरम, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन्स पर पैमाने पर काम किया है. वह डोकलाम गतिरोध को संभालने और भारत की सुरक्षा को लेकर रणनीति तय करने शामिल रहे. 1999 में कंधार में IC-814 विमान अपहरण संकट के दौरान बात करने वाले अधिकारियों में शामिल रहे।

अब केरल की बारी है, यहां भी बनेगी भाजपा की सरकार : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि केरल में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी. उन्होंने रविवार (11 जनवरी, 2026) को तिरुवनंतपुरम में कहा कि केरल में बीजेपी का समर्थन लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी इस साल होने वाले आगामी राज्य चुनावों में सरकार बनाएगी.

'केरल की जनता बीजेपी के समर्थन में

गृहमंत्री ने केरल में सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) पर भी जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने बीजेपी के बढ़ते वोट शेयर और हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में मिली जीत का भी जिक्र किया है. साथ ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में बढ़ते जनसमर्थन पर कार्यकर्ताओं का आभार जाताया है. गृहमंत्री ने यह बातें एक सभा को संबोधित करते हुई जनता के सामने की है. उन्होंने कहा, 'केरल की जनता बीजेपी को अपना समर्थन दे रही है. हमारा समर्थन बढ़ रहा है. 2014 में, हमें 11% वोट मिले थे, साल 2019 में, 16% हो गया और 2024 में इसका प्रतिशत 20 तक पहुंच गया है. अब यह वोट शेयर 20% से 30% और 40% तक पहुंचेगा. हम इसे 2026 में साबित करेंगे. उन्होंने कहा, 'हमने यह पूरे देश में पहले ही हासिल कर लिया है. अब केरल की बारी है. केरल में निश्चित रूप से बीजेपी का मुख्यमंत्री चुना जाएगा. केरल में यह बदलाव सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है.' हमने 30 ग्राम पंचायतें, दो नगरपालिकाएं जीती हैं, और हमारे मेयर अभी तिरुवनंतपुरम में सेवा दे रहे हैं.'गृहमंत्री ने कहा कि जीत का यह सफर सिर्फ हमारे सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के बलिदान की वजह से संभव हो सका है।

अस्पताल से डिस्चार्ज हुईं सोनिया गांधी, घर पर ही चलेगा इलाज

नई दिल्ली। कांग्रेस की संसदीय दल की चेयरपर्सन और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को रविवार (11 जनवरी, 2026) की शाम पांच बजे सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. दरअसल, ठंड और प्रदूषण के कारण ब्रोंकियल अस्थमा से जुड़े लक्षण बढ़ने पर उन्हें पिछले हफ्ते सोमवार (5 जनवरी, 2026) को भर्ती कराया गया था.सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने कहा कि डॉक्टरों की देखरेख में इलाज के बाद सोनिया गांधी की सेहत में तेजी से सुधार हुआ है. वह इलाज पर अच्छी तरह प्रतिक्रिया दे रही थीं और अब आगे का उपचार उनके आवास पर जारी रहेगा.सोनिया गांधी को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद 5 जनवरी, 2026 को रात करीब 10 बजे नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों का कहना था कि प्रदूषण और ठंडे मौसम के कारण सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उनकी स्थिति में गिरावट देखने को मिली थी. डॉक्टरों ने अपनी जांच में पाया कि उनका ब्रोंकियल अस्थमा हल्का बढ़ गया था।

अंतरिक्ष में जाएगी भारत की एक्स-रे नजर

ISRO नए साल पर पहला धमाका करने के लिए तैयार!

नई दिल्ली। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो नए साल पर पहला धमाका करने के लिए तैयार है. सोमवार सुबह श्रीहरिकोटा से एक ऐसा रॉकेट उड़ान भरेगा जो भारत को वो ताकत देने वाला है जिसे दुनिया स्पेस इंटेलिजेंस कहती है. 12 जनवरी की सुबह 10:17 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C62 मिशन लॉन्च किया जाएगा. यह मिशन भारत की सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है. इस मिशन का मुख्य आकर्षण EOS-N1 उपग्रह है जिसे कोड-नाम 'अन्वेषण' (Anvesha) दिया गया है.

इस रॉकेट में भारत का PSLV-C62 अपने साथ ले जा रहा है EOS-N1 यानी ऐसा उपग्रह जो धरती की सिर्फ तस्वीर नहीं लेगा बल्कि उसकी असलियत पढ़ेगा. यह भारत को वो ताकत देने वाला है जिसे दुनिया स्पेस इंटेलिजेंस कहती है ! यह सैटेलाइट साधारण कैमरे की तरह रंग नहीं देखता बल्कि रोशनी के सैकड़ों शेड्स को पढ़कर जमीन की खास रिपोर्ट तैयार करता है. मतलब मिट्टी के नीचे नमी है या सूखा, जंगल में हरियाली है या छलावा, कहीं नकली कैंप है या असली गतिविधि सबका सच अलग-अलग सिग्नेचर से पकड़ में आएगा.

दुश्मन के लिए बुरी खबर

EOS-N1 ऐसा निगरानी तंत्र है जो छुपे ठिकानों, नकली छलावरण और संदिग्ध हलचलों को पहचान सकता है. पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तान में छिपी गतिविधियां भी इसके हाइपरस्पेक्ट्रल डिजिटल फिंगरप्रिंट से बच नहीं पाएंगी. मतलब अब सिर्फ देखना नहीं पहचानना भी आसान. ये सैटेलाइट बताएगा कि किस खेत में पानी की कमी है, कहां फसल बीमार है और कहां सूखे का खतरा मंडरा रहा है. चक्रवात, बाढ़ और जंगल की आग से पहले चेतावनी मिलेगी ताकि तबाही से पहले तैयारी हो सके. PSLV-C62 सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के उपग्रहों को लेकर उड़ रहा है. यूरोप, ब्राजील, नेपाल, थाईलैंड सब इस उड़ान में सवार हैं. इसके साथ एक खास री-एंट्री कैप्सूल भी जाएगा जो भविष्य की स्पेस वापसी तकनीक का ट्रायल करेगा।

हर्षित के ऑलराउंड खेल से जीता भारत

शतक से चूके कोहली लेकिन तोड़ा संगकारा का रिकार्ड

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2026 की शुरुआत जीत से की. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया. इस जीत से भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. भारत की जीत में हर्षित राणा के ऑलराउंड खेल के अलावा विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के साथ केएल राहुल ने अहम भूमिका निभाई. हर्षित ने 2 विकेट लेने के अलावा निचले क्रम में आकर 29 रन की कीमती पारी भी खेली. कोहली अपना 85वां इंटरनेशनल शतक 7 रन से चूक गए जबकि शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी जड़ी वहीं श्रेयस अय्यर काइल जेमिसन ने अर्धशतक से रोक दिया. श्रेयस एक रन से अपना अर्धशतक चूक गए. सीरीज का दूसरा वनडे राजकोट में 14 जनवरी को खेला जाएगा.

301 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 49 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 306 रन बनाकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया. रोहित और गिल ने टीम इंडिया को सतर्क शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी की. रोहित शर्मा 29 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 650 छक्के पूरे कर लिए. इसके बाद गिल को विराट कोहली का साथ मिला. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी की. गिल 71 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हुए.

विराट कोहली ने सबसे तेज 28000 रन बनाए

विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28000 रन बना लिए. विराट ने इस आंकड़े पर पहुंचने वाले पारियों के लिहाज से सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सबसे कम पारियों में विराट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल की. कोहली को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 25 रन की जरूरत थी. इसके अलावा विराट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में सचिन के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए. उन्होंने कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा.

मुस्तफिजुर बाहर, लेकिन बांग्लादेशी अंपायर को भारत आने की मिली छूट

नई दिल्ली। पिछले दिनों भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड्स के बीच तनातनी बढ़ी है. यह पूरा विवाद वहां से शुरू हुआ, जब BCCI के निर्देश पर KKR फ्रैंचाइजी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) तो अपने देश में IPL के प्रसारण पर भी रोक लगा चुका है. यहां तक कि उसने अपने टी20 वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में करवाए जाने की मांग की है.

इस सबके बीच वडोदरा में भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच खेला गया, जिसके मैच ऑफिशियल्स यानी अंपायरों की लिस्ट में बांग्लादेश के शरफुद्दौला साइकत का भी नाम है. शरफुद्दौला, भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में थर्ड अंपायर की भूमिका में हैं.एक तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC को लिखे पत्र में भारत में अपने खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट की थी. तो आखिर ऐसा कैसे हो गया कि बीसीबी ने अपने अंपायर को भारत आने से नहीं रोका. जानिए क्या है इसको लेकर ICC का नियम?

बांग्लादेशी अंपायर, भारत कैसे आया?

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में जो भी अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हैं, वे ICC के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंपायरों को 2 श्रेणियों में बांटता है. अंपायरों को आईसीसी एलीट पेनल और आईसीसी इंटरनेशनल पेनल श्रेणियों में बांटा जाता है.

इन अंपायरों की नियुक्ति ICC करता है और उन्हें निकाल भी आईसीसी ही सकता है. इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अंपायर किस देश का होगा और कौन होगा, यह बीसीसीआई, बीसीबी या किसी अन्य देश का क्रिकेट बोर्ड तय नहीं करता है. यह काम ICC का है, इसलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता तो भी शरफुद्दौला को भारत आने से नहीं रोक सकता था.

आ रहा है रिलायंस जियो का धाकड़ IPO

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस जियो साल 2026 की पहली छमाही में अपना आईपीओ लेकर आ सकती है. हाल ही में हुई रिलायंस AGM में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जून 2026 तक कंपनी के शेयरों को लिस्ट कराने के अपने प्लान का जिक्र किया था. कई इंवेस्टमेंट बैंकरों के लगाए गए अनुमान के मुताबिक, , रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन 130 बिलियन डॉलर से 170 बिलियन डॉलर के बीच है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीओ के जरिए रिलायंस ग्रुप की यह कंपनी अपनी 2.50 परसेंट की हिस्सेदारी बेचकर 4.5 अरब डॉलर जुटा सकती है. इसी के साथ यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है. 2025 में ह्युडई मोटर इंडिया 3.3 अरब डॉलर का आईपीओ लेकर आई थी।

पंत चोट के कारण न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर, ध्रुव जुरेल को मौका

नई दिल्ली। ऋषभ पंत चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है। इसकी जानकारी BCCI ने रविवार को दी।शनिवार शाम अभ्यास सत्र के दौरान पंत थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे।इसी दौरान एक गेंद उनके पेट की दाहिनी तरफ जा लगी। गेंद लगते ही पंत दर्द में जमीन पर बैठ गए। इसके बाद टीम का सपोर्ट स्टाफ और मेडिकल टीम उन्हें मैदान से बाहर ले गई। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि पंत की दाहिनी पसली में खिंचाव आ गया है, जिस वजह से उन्हें आराम की जरूरत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह इस मैदान पर पहला मेंस इंटरनेशनल मैच होगा। दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट में और तीसरा वनडे 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ अपडेटेड वनडे स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)।

वार्मअप मैच में वैभव ने 50 गेंदों पर 96 रन बनाए

नई दिल्ली। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 से पहले खेले गए वॉर्म-अप मैच में भारत ने स्कॉटलैंड को DLS पद्धति से 121 रन से हरा दिया। यह मुकाबला शनिवार को खेला गया।मैच के हीरो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी रहे। उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों पर 96 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 7 छक्के लगाए। वैभव शतक से सिर्फ चार रन दूर रह गए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 374 रन बनाए। बारिश के कारण स्कॉटलैंड को 24 ओवर में 234 रन का लक्ष्य मिला। इसके जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 9 विकेट पर 112 रन ही बना सकी।सूर्यवंशी के अलावा तीन अन्य बल्लेबाजों ने फिफ्टी लगाए वैभव सूर्यवंशी के अलावा इस मैच में भारत के लिए विहान मल्होत्रा ने 77, एरन वर्गीज ने 61 और अभिग्यान कुंडू 55 रन बनाए। वहीं, खिलान पटेल ने 4 रन देकर 3 विकेट, दीपेश देवेंद्रन ने 14 रन देकर 3 विकेट लिए।

D- Mart को तीसरी तिमागगी में 856 करोड़ का मुनाफा

नई दिल्ली। D-Mart के नाम से देशभर में रिटेल चेन चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने शनिवार को फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए अपने तीसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया. इस दौरान कंपनी ने न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमाया, बल्कि रेवेन्यू, ऑपरेशनल रेवेन्यू में भी अच्छी-खासी ग्रोथ देखी गई. दिसंबर तिमाही में कंपनी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 18.3 परसेंट बढ़कर 855.92 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 723.72 करोड़ रुपये था. इस बीच, ऑपरेशंस से रेवेन्यू में भी 13.3 परसेंट की सालाना बढ़ोतरी देखी गई. इस तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 18,100.88 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की तीसरी तिमाही में 15,972.55 करोड़ रुपये था. Q3FY26 में PAT मार्जिन 4.7 परसेंट रहा, जबकि Q3FY25 में यह 4.5 परसेंट था।

लोन देने से पहले बैंक अन्य बातों पर भी देते हैं ध्यान

अच्छे क्रेडिट स्कोर के बाद भी क्यों अटक जाता है लोन?

नई दिल्ली। लोगों की बदलती जीवनशैली के साथ-साथ उनकी आर्थिक जरूरतें भी बदल रही हैं. अब सीमित संसाधनों में जीवन बिताने की बात पुरानी लगने लगी है. अपने जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेना आज एक सामान्य बात हो गई है. कुछ लोग घर खरीदने के लिए तो कुछ नई कार खरीदने के लिए लोन का सहारा लेते हैं. वहीं बहुत से लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन का सहारा ले रहे हैं. ऐसे में लोन लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का एक जरिया बन गया है.

हालांकि, कई लोग बैंक से लोन लेने से पहले सोचते हैं कि अगर उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और उनकी इनकम भी अच्छी है तो लोन आसानी से मिल जाएगा. लेकिन यह सोचना एक बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि लोन देने के लिए बैंक कई अन्य चीजों पर भी ध्यान देते हैं. इसलिए सिर्फ अच्छी आय और अच्छा क्रेडिट स्कोर होने भर से लोन मिलने की गारंटी नहीं होती. आइए जानते हैं, बैंक और कौन सी चीजों के आधार पर लोन देती हैं.

बैंक सिर्फ क्रेडिट स्कोर और इनकम ही नहीं देखते. बल्कि यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राहक अपने पैसों को कैसे खर्च करता है. बैंक यह देखते हैं कि हर महीने कमाई का कितना हिस्सा खर्च हो रहा है और कितनी बचत की जा रही है. अगर इनकम अच्छी है लेकिन पूरा पैसा खर्च हो जाता है और बचत नहीं दिखती, तो बैंक लोन देने में हिचकिचाते हैं.वहीं दूसरी तरफ, जिन लोगों की कमाई सीमित होती है. लेकिन वे खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं और नियमित बचत करते हैं. उन्हें बैंक ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं. इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखकर यह भी जांचते हैं कि खाते में पैसा कितनी नियमितता से आता है और कितनी जल्दी निकल जाता है. बैंक लोन जल्दी अप्रूव करवाने के लिए आपको अपने सभी बिल समय पर भरने चाहिए. साथ ही क्रेडिट कार्ड का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए. एक अच्छा क्रेडिट स्कोर लोन मिलने की संभावना को बढ़ा देता है.

वीबी-जी रामजी योजना पर भाजपा ने बनाई रणनीति

ग्रामीण इलाकों में हर घर में देंगे दस्तक, जिला स्तर पर कार्यशाला और गांवों में लगेगी चौपाल

रायपुर। मोदी सरकार की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) योजना को ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए भाजपा की प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला राजधानी रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रही है।कार्यशाला में सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और योजना के प्रचार-प्रसार के लिए गठित टोलियों के सदस्य शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान योजना को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर कार्यशालाएं और ग्रामीण स्तर पर चौपाल आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

जिला और पंचायत स्तर तक पहुंचने पर फोकस

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में ग्रामीण और पंचायत क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की जा रही है। पार्टी नेताओं की ओर से कार्यकर्ताओं को यह बताया जा रहा है कि योजना की जानकारी लाभार्थियों तक कैसे पहुंचाई जाए और किस स्तर पर संपर्क अभियान चलाया जाए।कार्यशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, नवीन मार्कंडेय सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद हैं।

वीबी-जी रामजी योजना की रूपरेखा पर चर्चा

बैठक के दौरान विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।इसमें बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाकर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में यह योजना अहम भूमिका निभा सकती है।कार्यशाला में बताया गया कि वीबी-जी रामजी योजना के तहत मनरेगा में मौजूद कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। योजना के अंतर्गत रोजगार दिवसों की संख्या बढ़ाकर 125 कर दी गई है। इसके साथ ही मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किए जाने का प्रावधान है।तय समय में भुगतान नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को ब्याज देने का प्रावधान भी रखा गया है। कार्यशाला के जरिए पार्टी संगठन को गांव-गांव तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और आगामी कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है।

मनरेगा को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज से मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत सार्वजनिक विरोध कर रही है। शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सुबह से शाम तक गांधी की मूर्ति के पास उपवास पर बैठ गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि, यह कदम केंद्र सरकार के मनरेगा में किए गए संशोधनों और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर पड़ रहे असर के विरोध में उठाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कहा कि, सरकार सुनियोजित तरीके से मनरेगा को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। उनके मुताबिक मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर सीधा हमला है।

मूल भावना को समाप्त करने की कोशिश

देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी और सम्मानजनक जीवन का आधार रहा है, लेकिन नई योजनाओं के जरिए इसकी मूल भावना को खत्म करने की

कोशिश की जा रही है। उन्होंने VB-G RAM G योजना का हवाला देते हुए कहा कि इससे मनरेगा के संवैधानिक अधिकार कमजोर होंगे और ठेकेदारी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के दौरान मनरेगा के बजट में कटौती, मजदूरी भुगतान में देरी और राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं।

'छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा' शुरू करेगी आप

20 हजार से ज्यादा गांवों तक पहुंचने का दावा, 450 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त

रायपुर। आम आदमी पार्टी आज से छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तरीय 'छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा' की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी का दावा है कि, यह यात्रा प्रदेश के 20,363 गांवों और 11,664 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी। अभियान का मकसद संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और जनता से जुड़ना है।

आप के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने बताया कि, पिछले दो महीनों से पार्टी संगठन को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी, विभिन्न प्रकोष्ठों और जिला पदाधिकारियों के साथ हुई बैठकों के बाद विधानसभा वार ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी की गई है। जिससे यात्रा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके।उनके मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक और सह-प्रभारी मुकेश अहलावत के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में 450 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं के जरिए यात्रा को गांव-गांव तक ले जाने की रणनीति तैयार की गई है।

उत्तम जायसवाल का कहना है कि संसाधन सीमित हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह और संगठन की तैयारी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। उनका दावा है कि यात्रा के बाद आम आदमी पार्टी एक नए रूप में छत्तीसगढ़ की जनता के सामने नजर आएगी।पार्टी ने लोकसभा और जिला स्तर पर संगठनात्मक बैठकों को पूरा कर लिया है।

हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रधान-पाठक सस्पेंड

प्रश्न-पत्र में पूछा कुत्ते का नाम, ऑप्शन में 'राम' देने पर मचा था बवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कक्षा 4 थीं के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में 'मोना के कुत्ते के नाम' पर विवाद चल रहा है। इसके उत्तर के चार विकल्पों में 'राम' नाम भी शामिल था। अन्य विकल्प बाला, शेरू और 'कोई नहीं' दिए गए थे। ये प्रश्न पत्र रायपुर संभाग के बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिले में बांटा गया था।'राम' नाम को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। अब जांच के बाद शिक्षा विभाग ने पेपर तैयार करने वाली प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है, जबकि मॉडरेटर शिक्षिका को सेवा से पृथक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। टीचर्स ने लिखित में माफी भी मांगी है। उन्होंने स्पष्टीकरण में कहा कि, उनका उद्देश्य 'रामू (RAMU)' लिखने का था, लेकिन टाइपिंग में 'U' छूट गया और 'RAM' छप गया।

अब जांच के बाद शिक्षा विभाग ने पेपर तैयार करने वाली प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है, जबकि मॉडरेटर शिक्षिका को सेवा से पृथक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

झीरम जांच आयोग को लेकर बयानबाजी के बाद प्रभारी महामंत्री ने की कार्रवाई

विकास तिवारी 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रवक्ता विकास तिवारी को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई झीरम घाटी हमले से जुड़े बयान और न्यायिक जांच आयोग को लेकर की गई टिप्पणी के बाद की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, विकास तिवारी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर यह फैसला लिया गया। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
निष्कासन आदेश

इससे पहले विकास तिवारी कांग्रेस भवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने झीरम घाटी हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इस मामले से जुड़े अहम दस्तावेज हैं और वही लिफाफा कांग्रेस कार्यालय में सौंपा था। विकास तिवारी ने झीरम घाटी हमले की सच्चाई सामने लाने की बात कहते हुए एनआईए और झीरम जांच आयोग को पत्र लिखकर नार्को टेस्ट की मांग भी की थी। इस पत्र में भाजपा नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल होने के बाद पार्टी के भीतर विवाद गहरा गया था।

पद से हटाने के बाद नोटिस, अब निष्कासन

नार्को टेस्ट की मांग वाला पत्र सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने इसे पार्टी अनुशासन के खिलाफ माना। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर विकास तिवारी को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि, तिवारी के दिए गए दस्तावेज और स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद मामला आलाकमान के सामने रखा गया। जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर अब छह साल के निष्कासन की कार्रवाई की गई है। पार्टी के भीतर इस फैसले को अनुशासन बनाए रखने के सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस पर है कि इस कार्रवाई के बाद विकास तिवारी आगे क्या रुख अपनाते हैं।

छत्तीसगढ़ में 58% हुआ DA केंद्र के बराबर मिलेगा भत्ता

- 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा
- CM साय ने किया ऐलान, बोले- कर्मचारियों के हित में फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अधिकारी-कर्मचारियों को अब केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा। CM विष्णुदेव साय ने घोषणा की है।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता (DA) केंद्र सरकार के समान बढ़ाने की घोषणा की है। अब 55% से बढ़ाकर महंगाई भत्ता 58% कर दिया गया है। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।साथ ही कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। बढ़ती महंगाई के असर से कुछ राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के आठवें राज्य सम्मेलन के दौरान की है। डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद लंबे समय से मांग कर रहे कर्मचारी खुश नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के कई राज्य अभी भी केंद्र के महंगाई भत्ते से पीछे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के बराबर डीए देने का फैसला किया है। हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति सजग है। समय-समय पर उनके हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

5 महीने पहले भी बढ़ा था 3% DA

इसके पहले राज्य सरकार ने अधिकारी-कर्मचारी के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया था। प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने 3 मार्च को विधानसभा में साल 2025-26 के वार्षिक बजट में 53 प्रतिशत डीए किए जाने की घोषणा की थी। राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके 53 प्रतिशत कर दिया गया था।

सरकार पर सालाना 540 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा

सातवें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया गया, जबकि छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत बढ़ाया गया। यह बढ़ोतरी 1 मार्च, 2025 से लागू हुई। इसका भुगतान अप्रैल में मार्च 2025 की सैलरी के साथ शुरू हुआ। महंगाई भत्ते में इस 3% की बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना 540 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अलावा पेंशनभोगियों को 3 प्रतिशत महंगाई राहत देने से सालाना 108 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांग

1. मोदी की गारंटी अनुसार केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों और पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) दिया जाए।
2. मोदी की गारंटी अनुसार DA एरियर्स की राशि कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित की जाए।
3. सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
4. लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
5. प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए समस्त सेवा लाभ और नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन समयबद्ध पदोन्नति दिया जाय।
6. सहायक शिक्षकों और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
7. अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण की जाए।
8. प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू की जाए।
9. अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस की जाए।
10. दैनिक, अनियमित, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बने।
11. सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जाए।

जामगांव के प्रसंस्करण इकाई से चमकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

रायपुर। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (CPU) ग्रामीण रोजगार में वनोपज और औषधीय पौधों के संग्रह, प्रसंस्करण और मूल्य-वर्धन (value addition) के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों, खासकर महिलाओं, के लिए आय और रोजगार के नए अवसर पैदा करती है। दुर्ग जिला के पाटन विकासखंड के जामगांव एम में स्थापित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई ग्रामीण रोजगार, वनोपज प्रसंस्करण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड' के नाम से बाजार में उपलब्ध

यह इकाई लगभग 111 एकड़ क्षेत्र में विकसित की गई है, जहां छत्तीसगढ़ शासन और राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के माध्यम से वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों से वनोपज और औषधीय पौधों का क्रय, संग्रहण और प्रसंस्करण किया जा रहा है। यहां तैयार किए जा रहे हर्बल उत्पाद 'छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड' के नाम से बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है।

प्रसंस्करण इकाई से मिल रहा स्थानीय लोगों को रोजगार

प्रसंस्करण इकाई क्रमांक- 01 में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। यहां आंवला, बेल और जामुन से जूस, कैंडी, लच्छा, मुरब्बा, शरबत, पल्प और आरटीएस पेय जैसे शुद्ध हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों का विक्रय एनडब्ल्यूएफपी मार्ट और संजीवनी स्टोर के माध्यम से किया जाता है। इस इकाई ने मात्र एक वर्ष में लगभग 44 लाख रुपये मूल्य के उत्पादों का निर्माण और विक्रय कर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।

20 हजार मीट्रिक टन क्षमता का केंद्रीय वेयरहाउस

इकाई क्रमांक- 02 में चार बड़े गोदाम बनाए गए हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 20,000 मीट्रिक टन है। यहां राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त वनोपज का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। वर्तमान में कोदो, कुटकी, रागी, हर्रा कचरिया, चिरायता, कालमेघ, पलास फूल और साल बीज सहित विभिन्न वनोपज का संग्रह किया गया है। इन उत्पादों का विक्रय संघ मुख्यालय रायपुर द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इन दोनों इकाइयों के संचालन से अब तक 5,200 से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजित हो चुका है।

पीपीपी मॉडल पर हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट यूनिट की स्थापना

जामगांव एम में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना की गई है। यह यूनिट छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और स्फेयर बायोटेक कंपनी के संयुक्त प्रयास से बनी है, जिसका लोकार्पण वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वन मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा किया गया था। लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में बनी इस यूनिट में गिलोय, कालमेघ, बहेड़ा, सफेद मुसली, जंगली हल्दी, गुड़मार, अश्वगंधा और शतावरी जैसे औषधीय पौधों से अर्क निकाला जा रहा है। इन अर्कों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं और वेलनेस उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट के माध्यम से ग्रामीण संग्राहकों से वनोपज और औषधीय पौधों का पूर्ण क्रय सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे उन्हें उचित मूल्य और नियमित आय मिल रही है। इससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और नए रोजगार अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

सुकमा जिले में नीली क्रांति की नई शुरुआत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर स्थित सुकमा जिला अब कृषि एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और मार्गदर्शन में जिले में पारंपरिक धान खेती के साथ-साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर के निर्देशन में सुकमा जिले की पांच ग्राम पंचायतों में झींगा पालन की शुरुआत कर नीली क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भेलवापाल, झापरा, गोंगला, मुरातोंडा एवं गादीरास के कुल 17 तालाबों को झींगा पालन के लिए चयनित किया गया है। कृषकों को वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण देने हेतु कृषि विज्ञान केंद्र, मुरातोंडा में एक विशेष डेमोंस्ट्रेशन यूनिट की स्थापना भी की गई है।

हाल ही में मत्स्य विशेषज्ञ डॉ. संजय सिंह राठौर, मत्स्य विभाग के श्री डी.एल. कश्यप एवं एनआरएलएम जनपद सुकमा के संयोजक सहित विशेषज्ञ दल ने चयनित तालाबों का निरीक्षण कर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। अब तक जिले में कतला, रोहू, ग्रास कार्प एवं पेटला मछलियों का पालन किया जाता रहा है। झींगा पालन से स्थानीय कृषकों और मछुआरों की आय में वृद्धि होगी। यह पहल सुकमा को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।

मत्स्य पालन से आर्थिक समृद्धि की राह

मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम कपुआ में स्थित श्रीराम मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, चंद्रगढ़ी ने शासकीय योजनाओं के माध्यम से मत्स्य पालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित कर आर्थिक समृद्धि की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। समिति ने मछली पालन को व्यवसायिक स्वरूप प्रदान करते हुए उत्पादन में निरंतर वृद्धि की है और वर्तमान में इससे प्रतिवर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित की जा रही है।

समिति के सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10 सदस्यों के किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत कराए गए, जिससे पूंजी की सुलभता बढ़ी और उत्पादन लागत में कमी आई। इसके साथ ही, सदस्यों को 10 दिवसीय मत्स्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्रदान किया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप समिति ने लगभग 1.50 लाख रुपये की शुद्ध आय अर्जित की, जिससे सदस्यों की आजीविका में सुधार हुआ।

अभिनय के साथ जिन्होंने लेखन में भी बनाया अपना खास मुकाम

वैश्विक सिनेमा में सफलता पाने के बाद प्रियंका ने अपनी आत्मकथा 'Unfinished' के जरिए लेखिका के रूप में भी पहचान बनाई. यह किताब बरेली से हॉलीवुड तक के उनके सफर को बेहद संवेदनशील, ईमानदार और सशक्त अंदाज में पेश करती है. लीवुड में रचनात्मकता सिर्फ कैमरे के आगे तक सीमित नहीं है. कई मशहूर फिल्मी हस्तियों ने अभिनय से आगे बढ़कर अपनी बातों और अनुभवों को शब्दों में पिरोया है. दिल छू लेने वाली आत्मकथाओं से लेकर सामाजिक व्यंग्य, बच्चों की कहानियों और व्यक्तिगत सफर तक, इन सितारों ने साबित किया है कि उनका कहानी कहने का हुनर पन्नों पर भी उतना ही चमकदार है.

प्रियंका चोपड़ा जोनस

वैश्विक सिनेमा में सफलता पाने के बाद प्रियंका ने अपनी आत्मकथा 'Unfinished' के जरिए लेखिका के रूप में भी पहचान बनाई. यह किताब बरेली से हॉलीवुड तक के उनके सफर को बेहद संवेदनशील, ईमानदार और सशक्त अंदाज में पेश करती है.

ट्विंकल खन्ना

बॉलीवुड से साहित्य की दुनिया में सबसे सफल बदलावों में से एक है ट्विंकल खन्ना का सफर. उनकी किताबें 'Mrs Funnybones', 'The Legend of Lakshmi Prasad' और 'Pyjamas Are Forgiving' बेस्टसेलर रहीं. अब वह 'Mrs Funnybones Returns' लेकर आई हैं. उनकी बुद्धिमत्ता, व्यंग्य और सामाजिक दृष्टि ने उन्हें भारतीय साहित्य में एक अलग पहचान दिलाई है.

इमरान हाशमी

तेजतर्रार ऑन-स्क्रीन छवि के लिए जाने जाने वाले इमरान ने बिलाल सिद्दीकी के साथ मिलकर 'The Kiss of Life' लिखी. यह किताब उनके बेटे अयान की कैंसर से लड़ाई की भावनात्मक कहानी है, जिसमें मजबूती, उम्मीद और सच्चाई की झलक मिलती है.

अनुपम खेर

अनुपम खेर ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें 'The Best Thing About You Is You' और 'Lessons Life Taught Me, Unknowingly' प्रमुख हैं. इन किताबों में वहअपने जीवन के अनुभवों के साथ प्रेरक संदेश, आत्मचिंतन और सकारात्मकता का सार साझा करते हैं.

नसीरुद्दीन शाह

सशक्त अभिनेता और उतने ही गहरे लेखक, नसीरुद्दीन शाह ने 'And Then One Day' नामक आत्मकथा लिखी. यह किताब उनके संघर्षों, अभिनय के प्रति उनके दृष्टिकोण और जीवन के प्रति बेबाक नजरिए को बेहद दिलचस्प तरीके से उजागर करती है.

कल्कि कोचलिन

अपनी साहसिक भूमिकाओं के लिए मशहूर कल्कि ने 'Elephant in the Womb' सह-लेखन किया, जो मातृत्व पर आधारित एक ग्राफिक संस्मरण है. इसमें हास्य, ईमानदारी और संवेदनशीलता का बेहतरीन मिश्रण है.

आलिया भट्ट

आलिया ने बच्चों के साहित्य में कदम रखते हुए 'The Adventures of Ed-a-Mamma' लिखी. अपने पर्यावरण-संवेदनशील ब्रांड को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ऐसी कहानियां रचीं जो बच्चों में प्रकृति, करुणा और जागरूकता के मूल्यों को जगाती हैं.

सोनाली बेंद्रे

पुस्तक-प्रेमी और अब लेखिका सोनाली ने 'The Modern Gurukul: My Experiments with Parenting' लिखी, जिसमें वे आज की तेज रफ्तार दुनिया में बच्चों की परवरिश को लेकर अपने अनुभव, परंपरा और जीवन के व्यावहारिक सबक साझा करती हैं.

हथखोज में अनूठी परम्परा का निर्वहन माता शक्ति लहरी

मकर संक्रांति पर्व पर गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर वि. खं. के ग्राम हथखोज में प्रति वर्ष माता शक्ति लहरी' मेले का आयोजन होता है। इस दिन मंदिर प्रांगण में पूजा-पाठ, भजन कीर्तन का आयोजन निरंतर चलते रहता है। अन्य स्थलों में आयोजित होने वाले मेलों की तरह यहां भी मनोरंजन के साधन, पकवान वख खान-पान सभी तरह के चीजें उपलब्ध रहती हैं।

इस मेले का विशेष महत्व है व्यक्तियों का नदी के सूखे रेत में लहरा लेना'। मंदिर प्रांगण के नीचे नदी के खुले रेत के विस्तारित भू-भाग पर कोई भी व्यक्ति रेत का जलहरी बनाकर उसे अपने माथे पर लगाकर दोनों हाथ जोड़ कर सीधे रेत पर लेट जाने के पश्चात कुछ क्षण बाद उसे स्वभाविक लहर आने लगता है। नदी के सूखे रेत पर वह दूर तक लहरा लेते हुए लुढ़कते रहता है जब तक कोई उसे रोके नहीं, तब तक वह लहर में मग्न रहता है। लहर के टूटने पर वह कुछ थकान महसूस करता है और उसे कुछ भी ज्ञात नहीं रहता। दूर दूर से लोग यहां आस्था का लहर लेने आते हैं।

इसे ग्रामीण माता शक्ति लहरी देवी की कृपा मानते हैं। यह आयोजन वर्ष में केवल एक बार श्मकर संक्रांतिर को ही होता है। कहा जाता है मंदिर के इस पवित्र स्थल पर सात नदी महानदी, पैरी, सोंढुर, सूखा नदी, बगनई नदी, केछवा नदी और सरगी नदी का संगम स्थल है। इस आस्था के पर्व का एक विज्ञान के अनुसार ऐसी शक्तियां खगोलीय घटना पर आधारित होती हैं। जब गुरु ग्रह, सूर्य और चन्द्रमा के विशेष संयोग में होता है तब मानव शरीर ग्रह व धरती के चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। बायो मॅग्नेटिज्म के अनुसार हथखोज के नदी के रेत पर जहां लोगों को लहरा आता है वह स्थल मानव शरीर पर चुम्बकीय क्षेत्रों का उत्सर्जन करता है और बाहरी ऊर्जा क्षेत्रों से प्रभावित होता है यह आस्था और मेले के दौरान अनुभव यह गर्व का विषय है कि हमारे पूर्वज खगोल शास्त्र व जैविक प्रभावों की गहन जानकारी रखतें थे तभी इस स्थल को शक्ति लहरी के लिए उपयुक्त माना। शायद यही कारण है कि हमारे पूर्वज इस स्थल को पवित्र मान कर शक्ति लहरी की उपमा दिया होगा।

गऊ दरहा में गौ हत्या से मिलती है मुक्ति

घनश्याम सिंह नाग

बस्तर अंचल की प्राचीन राजधानी बड़े डोंगर क्षेत्र में धार्मिक महत्व के अनेक स्थल देखे जा सकते हैं। इन स्थलों पर ग्रामीणों की आज भी काफी आस्था है। इन स्थलों में बड़े डोंगर से 12 कि मी दूरी पर बारदा नदी के तट पर शिव मंदिर से लगा एक जल कुंड को गऊ दरहा के नाम से जाना जाता है।

बताया जाता है कि इस कुंड का सीधा संबंध मंदिर से है, मंदिर में चढ़ाया गया फूल और पानी इस कुंड में पहुंच जाता है। शिव मंदिर में स्थापित नर मुण्डों की माला पहने मां काली की प्रस्तर प्रतिमा इसी कुंड से मिली है। जनश्रुति है कि एक मछुआरे ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से गऊ दरहा में जाल डाला था। जब जाल बाहर खींचा तो उसमें मछली के जगह मां काली की मूर्ति थी। मां काली की इस प्रतिमा को शिवलिंग के समीप स्थापित कर दिया गया है। जन मान्यता है कि जाने अनजाने में यदि किसी व्यक्ति से गौ हत्या हो जाए तो गौ हत्या के पाप से गऊ दरहा में मुक्ति मिलती है। कलंकित व्यक्ति गऊ दरहा के जल में खड़ा होकर गऊ दान करे तो वह गौ हत्या के महापाप से मुक्त हो जाता है। गौ हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए लोग यहां आते हैं इसलिए इस दरहा को गऊ दरहा कहा जाता है। इस कुंड के तल में सोने की शिवलिंग होने की धारणा भी ग्रामीणों में है।

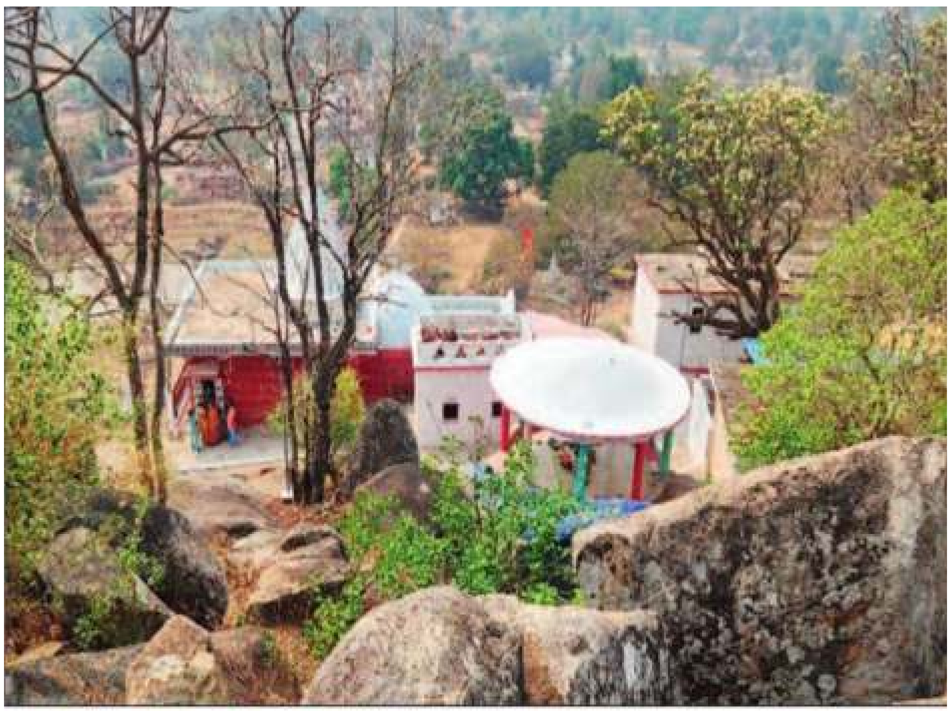

खैरागढ़ रियासत काल के साक्षी महंत तुलसीदास

वीरेन्द्र सिंह ठाकुर

अपने गुरु भाई ब्रह्म दास की हत्या के बाद महंत तुलसीदास ने कोंड़का (खैरागढ़) रियासत का कामकाज संभाला। सन 1780 में महंत तुलसीदास को नागपुर के राजा रघु जी राव द्वितीय ने कोंड़का जमींदारी की सनद प्रदान की और वे कोंड़का के मान्यता प्राप्त जमींदार हुए।

महंत तुलसीदास ने परपोड़ी के जमींदार दुर्जन साय और उसके भाई डोमन साय को मार कर अपने बड़े भाई महंत ब्रह्म दास की हत्या का बदला लिया। कबीर धाम जिले के बिडौरा नामक गांव के समीप खजरी नामक गांव में दुर्जन साय की समाधि है। साजा-परपोड़ी के बीच बोरतरा नामक गांव में एक चबूतरा है जिसे डोमन चौरा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं दोनों समाधियों में परपोड़ी के दोनों जमींदार भाइयों के कटे सिरों को दफनाया गया है। महंत तुलसीदास अपने गुरु महंत रूप दास और गुरु भाई महंत ब्रह्म दास के समान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सके और अपना विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। महंत तुलसीदास समीप के जमींदारों को बंधक के रूप में रुपए उधार देते थे। उधार की राशि अदा नहीं करने पर उसकी सीमा में धीरे धीरे कई गांव जुड़ने लगे। छुईखदान राजमहल का निर्माण उनके कार्यकाल में ही आरंभ हुआ। उनके इकलौता पुत्र महंत बाल मुकुंद दास हुए। महंत तुलसीदास जी ने' पाखण्ड मुख मंडन ' की रचना कर अपने पूर्वजों की तरह साहित्य साधना के क्रम को जारी रखा।

दो के बाद चार पैर वाले चूहे खा गए धान...

करोड़ों की शराब, गांजे के बाद करोड़ों का धान खा गए पेटू चूहे

- जिम्मेदारों ने बताया कवर्धा के चूहे सात करोड़ के धान खा गए
- स्टॉक के मिलान में खुलासा 26 हजार क्विंटल धान गायब
- बीते साल चूहों की वजह से धान खरीदी में 8000 करोड़ का नुकसान
- 25 साल में हजारों करोड़ के धान खाने वाले चूहों का खुलासा ही नहीं

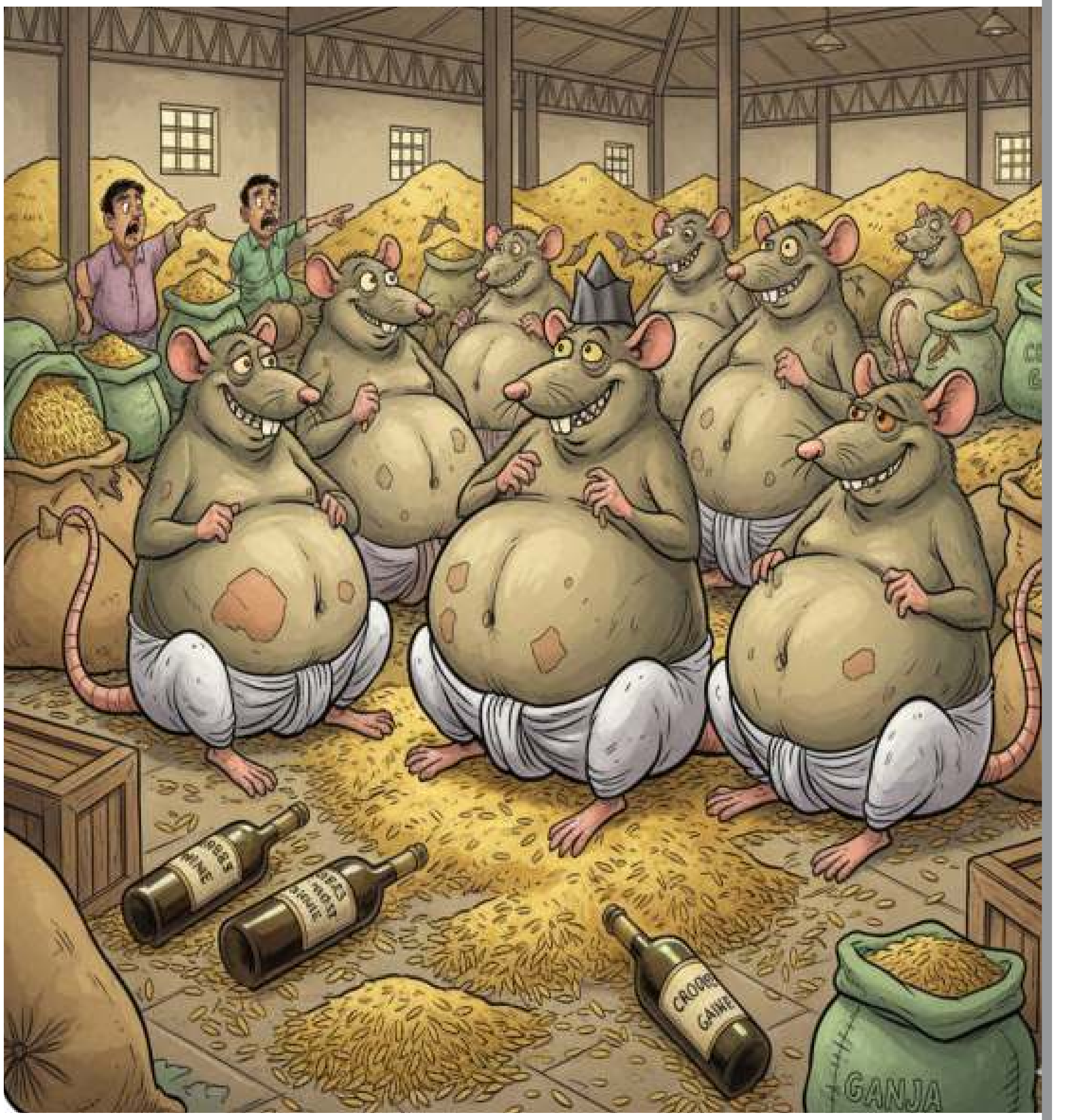

विशेष संवाददाता/शेख आबिद
मोबाईल नंबर 810982829

एक वक्त था कि विघ्नहर्ता गणेश की सवारी चूहों को मोदक ही पसंद थे। अब चार पैर वाले चूहे ऐबी और नशेड़ी होने के साथ पेटू भी हो गए हैं। पहले तो थानों में रखी शराब और जब्त गांजा चूहों ने चाट कर दिया। अब छत्तीसगढ़ के चूहे सरकारी धान गड़रगप्प कर दिए हैं। यह कारस्तानी दो पैर वाले चूहों की है या फिर चार पैर और छोटे पेट वाले चूहों की इसका खुलासा फ़िलहाल नहीं हुआ है। ख्याल होगा पिछले साल झारखंड की एक खबर बेहद चर्चा में थी चूहे 800 बोतल शराब गटक डाले तो एक करोड़ का गांजा पीकर मतवाले हो गए। मगर छत्तीसगढ़ के चूहे उनसे आगे निकल गए। छोटे मूसक 26 हजार क्विंटल धान कैसे खा सकते हैं? तो आपको यकीन करना होगा...चूहे ही धान चट किए हैं...भले ही वो दो पैर वाले चूहे क्यों न हो। पिछले साल ऐसे ही दो पैर वाले बेईमान चूहों की वजह से धान खरीदी में 8000 करोड़ का नुकसान हुआ था। क्या छोटे-छोटे चूहे 26 हजार क्विंटल धान खा सकते हैं?

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ सुशासन में एक असंभव सी खबर सुनने में आ रही है। सच से कोसों दूर लगने वाली ये खबर राजधानी रायपुर से 100 किलोमीटर दूर कवर्धा की है जहां चूहे सात करोड़ का धान खा गए। स्टॉक के मिलान में खुलासा हुआ कि 26 हजार क्विंटल धान गायब है। अकेले चारभाटा केंद्र से ही 22 हजार क्विंटल। अफसरों ने कहा, चूहे खा गए। 22 हजार क्विंटल धान करीब सात करोड़ के होते हैं। याने कवर्धा के चूहे सात करोड़ के धान खा गए। पिछले साल ऐसे ही कुछ भ्रष्टाचारियों की वजह से धान खरीदी में 8000 करोड़ का नुकसान हुआ था। स्थिति ऐसी आ गई है कि दो-एक साल बाद सरकार धान खरीदने की स्थिति में नहीं रहेगी। 38 हजार करोड़ मार्कफेड पर लोन हो गया है। पहले धान घोटाला, मिलर्स का फर्जीवाड़ा और अब चूहों का पेट भरने से सरकारी धान में खर्च किया जा रहा पैसा माल-ए-मुफ्त दिल बेरहम सा हो गया है।

रकबा लगभग उतना, खरीदी नौ गुना बढ़ी

सूबे में धान का रकबा लगभग उतना ही है, मगर खरीदी नौ गुना बढ़ गई। 2002-03 में 18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, पिछले साल यह 149 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया। राईस मिलों, धान घोटाले की ईडी जांच चल रही है। अब लगने लगा है कि आर्थिक गड़बड़ियों और शासन को हजारों करोड़ का नुकसान पहुँचाने वाले चूहों की भी जांच होगी तो चौंकाने वाला खुलासा होगा।

कलेक्टर हैं जिम्मेदार, अफसर संदिग्ध

धान खरीदी के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने इस बार सरकार ने बड़ी तैयारी की थी। कलेक्टरों की कई बार वीसी हुई। कलेक्टर कांफ्रेंस में भी आगाह किया गया। दावे किए गए इस बार ऐसी टेक्नालॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा कि धान खरीदी में पारदर्शिता रहेगी। ऐसे में गड़बड़ी करने वाले कामयाब नहीं होंगे। लेकिन चूहों ने सरकार को चुनौती दे ही दिया। चीफ सिकरेट्री विकास शील पूर्व में सचिव फ़ूड रह चुके हैं। बावजूद इसके उनके राज में चूहों की खुराक बढ़ गई है और जिम्मेदार कलेक्टरों से अब तक चीफ सेक्रेटरी ने राफ्ता नहीं रखा है।

धान चट करवाने वाले डीएमओ को नोटिस

चूहों के जरिये सात करोड़ के धान चट करवाने वाले डीएमओ को नोटिस दी गई है। डीएमओ का यह कहना भी गौरतलब है कि हमारे जिले की स्थिति काफी अच्छी है। याने बाकी जिलों की अगर जांच हो जाए तो फिर कयामत आ जाएगी। बहरहाल, जब तक दो-चार बड़े कौवे को मारकर नहीं लटकाया जाएगा, तब तक सरकार के लिए फर्जी धान खरीदी रोकना मुमकिन नहीं होगा।

धान रिसाइकिलिंग और राईस माफियाओं बेदर्द

10 अक्टूबर की विष्णुदेव कैबिनेट की बैठक में गहन चिंतन किया गया। फूड और मार्कफेड के अफसर प्रेजेंटेशन दे रहे थे और मंत्रिपरिषद सुन रही थी। बैठक में यहां तक बात आ गई कि अगर धान खरीदी की यही स्थिति रही तो एकाध साल बाद धान खरीदने की स्थिति नहीं रहेगी। आज की तारीख में मार्कफेड पर 38 हजार करोड़ का लोन है और इस साल ओवर परचेजिंग से राज्य के खजाने को 8 हजार करोड़ की चपत लग चुकी है। दरअसल, दिक्कत किसान और धान से नहीं, दिक्कत धान की रिसाइकिलिंग और राईस माफियाओं के खेल से है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का ग्राफ इस तेजी से बढ़ रहा कि अच्छे-अच्छे कृषि वैज्ञानिक हैरान हैं। पुराने लोगों को याद होगा, 2002-03 में मात्र 18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। 20 साल में यह नौ गुना बढ़ गई। जबकि, खेती का रकबा तेजी से कम हो रहा है। ये कहना भी कुतर्क होगा कि रेट बढ़ने से धान ज्यादा बोए जा रहे हैं। आखिर पहले भी सिर्फ धान ही बोया जाता था और कोई फसल लगाए नहीं जाते थे कि उसे बंद कर अब धान बोया जा रहा। जाहिर है, 2024-25 में सारे रिकार्ड तोड़ते हुए धान खरीदी 149 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गई।

एक्सपर्ट्स कहते हैं फर्जी खरीदी से बड़ा नुकसान

जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में वास्तविक धान 100 से 110 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए। याने बिचौलियों और अधिकारियों की मिलीभगत से की जाने वाली रिसाइकिलिंग और दूसरे प्रदेशों से आने वाले अवैध धानों को रोक दिया जाए तो सीधे-सीधे 30 से 35 लाख मीट्रिक टन की फर्जी खरीदी रुक जाएगी। बता दें, 2024-25 में भी लिमिट से अधिक खरीदी से धान का डिस्पोजल नहीं हो पाया और खुले बाजार में नीलामी से करीब दो हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल, पहली ही बार में पूरे लूज पोल तो बंद नहीं किए जा सकते। फिर भी अगर रिसाइकिलिंग और बिचौलियों पर अंकुश लगाकर 25 से 30 लाख मीट्रिक टन धान की फर्जी खरीदी अगर रोक दी गई तो खजाने का करीब 10 हजार करोड़ बचेगा, जो माफियाओं, राईस मिलरों, अधिकारियों और नेताओं की जेब में जाता है।

छग. में फसल चक्र परिवर्तन पर परहेज क्यों ?

छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी हमेशा कहते थे कि छत्तीसगढ़ में धान और गरीबी दोनों एक-दूसरे की पूरक है। मध्यप्रदेश के समय कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि छत्तीसगढ़ में खेती का ट्रेंड बदला जाए। राज्य बनने के बाद अजीत जोगी ने जरूर फसल चक्र परिवर्तन के तहत मक्का, मिलेट और दलहन-तिलहन के लिए कोशिशें शुरू की थीं। मगर इसके कुछ अरसा बाद ही सरकार बदल गई। फिर दो दशक में फसल चक्र कभी चर्चा में नहीं आया। जबकि, फैक्ट है कि दूसरी फसलें कई गुना ज्यादा आमदनी दे सकती हैं। धान में एकड़ पर 20 हजार से ज्यादा नहीं बचता, वहीं मिलेट या दूसरी फसलें लगाएं तो 40 से 50 हजार रुपए की बचत हो सकती है। राजनांदगांव में छुरिया और कांकेर के पखांजूर इलाके के किसान मक्का के अलावा कुछ लगा नहीं रहे हैं। ऐसा बाकी जिलों में भी किया जा सकता है। इसकी इसलिए भी जरूरत है कि 3100 रुपए में धान खरीदी के बाद भी छोटे किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। 85 से 90 परसेंट तो छोटे ही किसान हैं। जिनके पास दो-तीन, चार एकड़ जमीनें हैं। कोई बड़ा खर्च आ जाए तो उन्हें कर्ज ही लेना पड़ता है।

दो महिला आईएएस की सख्ती भी काम नहीं आई

राज्य सरकार ने धान खरीदी में भ्रष्टाचार को रोकने दो महिला आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी हैं। रीना बाबा कंगाले इस समय सिकरेट्री फूड और किरण कौशल एमडी मार्कफेड। सीएम सचिवालय ने इसकी प्लानिंग पहले ही कर ली थी। इसी रणनीति के तहत रीना बाबा साहेब कंगाले को रेवेन्यू का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसका फायदा यह हुआ कि उन्होंने राजस्व अमले से धान की फसल का क्रॉप सर्वे करा लिया। पटवारियों से गिरदावरी रिपोर्ट भी ले ली गई। अभी तक जिन खेतों में एकड़ में 15 क्विंटल धान नहीं होते थे, वहां 21 क्विंटल का क्लेम किया जा रहा था।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27